संयम ◆संस्कार ◆संतुलन

R.N.I. No.-UPHIN/2004/22466

शहर समता

वर्ष-23 अंक- 44
पृष्ठ 8
शुक्रवार
30 अक्टूबर 2026
प्रातः संस्करण
हिन्दी दैनिक
प्रयागराज
मूल्य-1.00

प्रयागराज से प्रकाशित Email : shaharsamta@gmail.com Website : https://Shaharsamta.com

सम्पादक-उमेश चन्द्र श्रीवास्तव

विविध- बदलते मौसम में बीमारियों से...

विचार- स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए एक और...

खेल- टीम इंडिया के ओपनर अभिषेक...

योगी सरकार ने बदले कैरेक्टर सर्टिफिकेट के कई नियम

अब हिंसा में शामिल युवाओं को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी



- सिर्फ एफआईआर दर्ज होने से नहीं होंगे अपात्र
- सत्यापन लंबित होने पर भी मिल सकेगा नियुक्ति पत्र

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन की नीति सख्त कर दी गई है। अब हिंसक तरीकों से व्यवस्था बदलने यानी 'रिजीम चेंज' के उद्देश्य वाले संगठनों से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माना जा सकता है। प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों, परिषदों और स्थानीय निकायों में सीधी भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों पर यह नीति लागू होगी। शासनादेश के मुताबिक, ऐसे संगठन के सदस्य, जिसका घोषित उद्देश्य हिंसक तरीकों से व्यवस्था बदलना है, सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। हालांकि, केवल राजनीतिक विचारधारा के आधार पर किसी अभ्यर्थी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज की ओर से यह शासनादेश हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है। नई नीति में स्पष्ट किया गया है कि किसी अभ्यर्थी के खिलाफ केवल एफआईआर दर्ज होने या जांच लंबित रहने से उसे स्वतः अयोग्य नहीं माना जाएगा। अंतिम रूप से बरी होने, समझौते से निपटे मामलों और किशोर न्याय कानून के दायरे में आने वाले मामलों में भी स्वतः अयोग्यता लागू नहीं होगी। हालांकि, हत्या, डकैती, दुष्कर्म, महिला की गरिमा भंग करने, भ्रष्टाचार, आतंकवादी गतिविधियों, पेपर लीक और सॉल्वर गैंग से जुड़े मामलों में संलिप्तता सामने आने पर अभ्यर्थी की पात्रता प्रभावित हो सकती है। चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट लंबित होने के कारण नियुक्ति पत्र रोकना अनिवार्य नहीं होगा। अभ्यर्थी से स्व-घोषणा पत्र और निर्धारित प्रपत्र लेकर औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी किया जा सकेगा। हालांकि, गलत जानकारी देने या सत्यापन में अपात्र पाए जाने पर नियुक्ति तत्काल रद्द की जा सकती है। संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों का नए सिरे से चरित्र सत्यापन नहीं कराया जाएगा। जरूरत पड़ने पर उनके पिछले विभाग से आवश्यक जानकारी ली जा सकती है।

डिजिटल धोखाधड़ी: बैंक चूके तो करनी होगी पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई



नई दिल्ली, एजेंसी। डिजिटल गिरफ्तारी के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बैंकों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। इस बीच, व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने अब तक 9,400 संदिग्ध खातों को प्रतिबंधित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक के केवाईसी संशोधन निर्देशों की जांच करने की बात कही है। ये निर्देश 31 दिसंबर तक लागू किए जाने हैं। न्यायालय ने यह भी साफ किया कि ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी होने पर बैंकों का ग्राहकों के प्रति कर्तव्य है। उन्हें असामान्य लेनदेन के बारे में पड़ोसी पुलिस थानों को तुरंत सूचित करना चाहिए। यह कदम डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने और पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। धोखाधड़ी के मामलों में उनकी निष्क्रियता स्वीकार्य नहीं होगी। यह सुनिश्चित करना बैंकों की प्राथमिकता होनी चाहिए कि उनके ग्राहक सुरक्षित रहें। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि बैंकों द्वारा उचित सावधानी बरतने में विफलता के कारण किसी ग्राहक को डिजिटल धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है, तो वित्तीय संस्थानों को पीड़ित के नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने एक स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वित्तीय संस्थानों का यह प्राथमिक वैधानिक कर्तव्य है कि वे अपने ग्राहकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों के पीड़ितों को कम से कम उनकी गँवाई गई पूरी राशि का मुआवजा मिलना चाहिए, यदि धोखाधड़ी बैंक की ड्यू डिलिजेंस में चूक का परिणाम पाई जाती है। इसके अलावा, शीर्ष अदालत ऐसे मामलों में जिम्मेदार बैंकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के निर्देश देने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

पीठ ने बैंकों के लिए अनिवार्य निवारक उपायों पर जोर देते हुए कहा कि:

असामान्य लेन-देन पर रोक: खाताधारक के स्थापित ट्रांजैक्शन पैटर्न से विचलन करने वाले किसी भी अस्वाभाविक लेन-देन को तुरंत अस्थायी रूप से निलंबित किया जाना चाहिए।

ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग: संदिग्ध गतिविधियों की स्वचालित रिपोर्टिंग और लेन-देन की प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए भौतिक सत्यापन लागू किया जाए।

पुलिस को सूचना: डिजिटल अरेस्ट के संदिग्ध शिकार बने ग्राहकों से जुड़े अस्वाभाविक लेन-देन के बारे में नजदीकी पुलिस स्टेशनों को तुरंत सचेत करना बैंकों की जिम्मेदारी होगी।

शाह ने चक्रवात 'अर्नब' के मद्देनजर आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बात की

नयी दिल्ली, एजेंसी। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के मद्देनजर गुरुवार को आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बात कर स्थिति की जानकारी ली है। श्री शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। गृह मंत्री ने कहा , चक्रवात 'अर्नब' के मद्देनजर आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बात की है। इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस आपदा के समय लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सक्रियता के साथ युद्धस्तर पर बचाव व राहत कार्य कर रही हैं। आपदा के प्रभाव का आंकलन करने और आगे की आवश्यक सहायता तय करने के लिए जल्द ही अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय टीमें भेजी जायेंगी। भारत सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लोगों के साथ खड़ी है। उल्लेखनीय है कि श्अर्नबश ने बुधवार सुबह आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक दी थी। इस तूफान से आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और पुडुचेरी बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। तूफान के कारण आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भारी बारिश हुई, 125 से 150 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चली। प्रभावित क्षेत्रों से करीब एक लाख 80 हजार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तूफान से जनजीवन अस्त वयस्त हुआ है और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। तट से टकराने के बाद अर्नब अब कमजोर होकर गहरे दबाव में बदल चुका है।



पीएम मोदी गुजरात में 14 हजार करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात

पीएम किसान की 24वीं किस्त भी होगी जारी



नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वह 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री अपने गुजरात प्रवास के दौरान ही 'पीएम-किसान' योजना के तहत 19,000 करोड़ रुपये की 24वीं किस्त जारी करेंगे और दो ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध एकता नगर का दौरा भी करेंगे, जहां वह सांस्कृतिक और पर्यटन महोत्सव 'भारत पर्व 2026' का उद्घाटन करेंगे और नर्मदा आरती में शामिल होंगे। मोदी शुक्रवार को गुजरात पहुंचने के बाद सबसे पहले बनासकांठा में 'एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी-इन विट्रो फर्टिलाइजेशन' प्रयोगशाला और 'भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर' का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री बनासकांठा में 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। साथ ही वह 'पीएम-किसान' योजना के तहत 19,000 करोड़ रुपये की 24वीं किस्त जारी करेंगे और दो ट्रेन सेवाओं की शुरुआत करेंगे। मोदी का बनासकांठा में एक जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। मोदी 31 अक्टूबर को एकता नगर में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और 400 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद एकता नगर में वर्षा वन और वामन वृक्ष वाटिका का दौरा करेंगे और सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे। मोदी अपने गुजरात प्रवास के दौरान अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2ए और चरण 2बी की आधारशिला रखेंगे। अमहदाबाद मेट्रो के चरण 2ए की लंबाई छह किलोमीटर से अधिक होगी, जिसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे के बीच पांच स्टेशन होंगे, जबकि चरण 2बी की लंबाई 3.3 किलोमीटर से अधिक होगी, जिसमें गिफ्ट सिटी से शाहपुर तक के तीन स्टेशन शामिल होंगे।

बाम्बे हाई कोर्ट से इमरान खान को राहत, भारत छोड़ो नोटिस पर लगी रोक

मुंबई, एजेंसी। अभिनेता इमरान खान, जिनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड है, ने अधिकारियों से उन सबूतों को साझा करने के लिए कहा है, जिनके आधार पर वे उनका कार्ड रद्द करने पर विचार कर रहे हैं। गुरुवार को खान ने फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस द्वारा जारी लीव इंडिया नोटिस (भारत छोड़ने का नोटिस) को चुनौती दी। मुंबई पुलिस द्वारा एक विरोध प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिए जाने के बाद, इस नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब इस नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी है। 22 अक्टूबर के एक पत्र में खान ने थ्त्त् को बताया कि 17 अक्टूबर को उन्हें जो श्शो-कॉज़ नोटिसश (कारण बताओ नोटिस) जारी किया गया था, उसमें मुंबई पुलिस द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों और एक रिपोर्ट का जिक्र था। हालांकि, उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने ये दस्तावेज उनके साथ साझा नहीं किए थे। श्शो-कॉज़ नोटिसश में किसी व्यक्ति से यह स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।

आतंकवाद से निपटने का अनुभव आसियान देशों से साझा करेगा भारत : राजनाथ

नयी दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का अपना जमीनी अनुभव आसियान देशों के साथ साझा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत ने दशकों तक सीमा पार आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करके यह अनुभव हासिल किया है। ऑपरेशन सिंदूर



ने भारत की सक्रिय और जमीनी अनुभव पर आधारित रणनीति को दिखाया। श्री सिंह ने गुरुवार को फिलीपींस के सेबू में आसियान रक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक (एडीडीएम-प्लस) को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती। भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण और खुफिया जानकारी साझा करके सहयोगी देशों की आतंकवाद से निपटने की क्षमता मजबूत करने के लिए तैयार है। भारत और मलेशिया 2024 से 2027 तक आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ कार्य समूह की सह-अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए समुद्री सहयोग को भी अहम बताया। उन्होंने कहा कि समुद्री रास्तों पर जहाजों की आवाजाही और विमानों की उड़ान की स्वतंत्रता पर भारत का जोर किसी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि क्षेत्र के सभी देशों के साझा हितों की रक्षा के लिए है।

PRESS
हमेशा आपके साथ

दैनिक एवं साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र

शहर समता
संयम ★ संस्कार ★ संतुलन

Website
www.shaharsamta.com

Subscribe on YouTube
youtube.com/@shaharsamtanews

सही खबर, सही समय पर

स्थापित 2001 • RNI Dainik UPHIN/2004/22466 • साप्ताहिक UPHIN/2001/03996 • कार्यालय 289/238 A कर्नलगंज प्रयागराज • संपर्क 9005239332, 9450482227

एंबुलेंस बुलाने का सबूत नहीं दे पाना हत्या साबित करने का आधार नहीं, कोर्ट ने पति को किया बरी

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एंबुलेंस बुलाने का सबूत नहीं दे पाना हादसे को हत्या साबित करने का आधार नहीं माना जा सकता। हत्या का आरोप सिद्ध करना अभियोजन की जिम्मेदारी है। बेगुनाही के सबूत का भार आरोपी पर नहीं थोपा जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एंबुलेंस बुलाने का सबूत नहीं दे पाना हादसे को हत्या साबित करने का आधार नहीं माना जा सकता। हत्या का आरोप सिद्ध करना अभियोजन की जिम्मेदारी है। बेगुनाही के सबूत का भार आरोपी पर नहीं थोपा जा सकता। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने पत्नी की हत्या में उम्रकैद पाए अनिल कुमार सागर की अपील स्वीकार कर ली। कोर्ट ने फर्रुखाबाद के ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए याची को बरी कर दिया। अभियोजन के अनुसार आठ सितंबर 2013 को आरोपी अपनी पत्नी के साथ बाइक से जा रहा था।

आरोप है कि नवाबगंज–वीरपुर मार्ग पर नगला झब्बू सिंह गांव के पास पत्नी की हत्या कर शव सड़क पर फेंक दिया। इसके बाद दावा किया कि वह शौच के लिए रुका था, तभी एक मिनी ट्रक ने उसकी पत्नी को टक्कर मार दी। उसने तत्काल परिजनों को सूचना दी। एंबुलेंस बुलाकर पत्नी को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

विवाहिता के मायकेवालों ने हत्या और सबूत मिटाने का मुकदमा दर्ज कराया। फर्रुखाबाद की विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 30 मार्च 2024 को दोषसिद्धि का फैसला सुनाया था। तीन अप्रैल 2024 को सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने पाया कि मृतका के पिता और भाई घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे। उनके बयान हत्या के आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मृतका के पिता की ओर से पुलिस अधीक्षक को दिया गया शिकायती पत्र घटना के बाद का था। उसकी मूल प्रति भी पेश नहीं की गई थी। मृतका के पोस्टमार्टम में शरीर पर 12 बाहरी चोटें मिली थीं। डॉक्टर ने माना कि ये चोटें वाहन दुर्घटना से भी आ सकती थीं।

ज्यादा किराया वसूलने के बाद भी पटरियों पर हांफ रहीं स्पेशल ट्रेनें, लेट लतीफी से बिगड़ रहा शेड्यूल

प्रयागराज। त्योहारी सीजन में स्पेशल ट्रेनें यात्रियों के लिए राहत के बजाय बड़ी मुसीबत बनती जा रही हैं। अधिक किराया चुकाने के बावजूद यात्रियों को न सिर्फ नियमित ट्रेनों के मुकाबले काफी लंबा सफर करना पड़ रहा है, बल्कि लेट–लतीफी से उनकी यात्रा का शेड्यूल भी बिगड़ रहा है। त्योहारी सीजन में स्पेशल ट्रेनें यात्रियों के लिए राहत के बजाय बड़ी मुसीबत बनती जा रही हैं। अधिक किराया चुकाने के बावजूद यात्रियों को न सिर्फ नियमित ट्रेनों के मुकाबले काफी लंबा सफर करना पड़ रहा है, बल्कि लेट–लतीफी से उनकी यात्रा का शेड्यूल भी बिगड़ रहा है। गुजरात के वेरावल से प्रयागराज आने वाली स्पेशल ट्रेन (04190) इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस ट्रेन को 27 अक्तूबर की शाम 7.50 बजे प्रयागराज पहुंचना था लेकिन यह निर्धारित समय से करीब 19.25 घंटे की देरी से 28 अक्तूबर की दोपहर 3.15 बजे जंक्शन पहुंची।

स्थिति यह थी कि यह ट्रेन अपने शुरुआती स्टेशन से ही साढ़े सात घंटे की देरी से रवाना हुई थी। इसमें सफर कर रहे यात्री मनोज प्रजापति ने बताया कि ट्रेन 27 अक्तूबर की दोपहर 12रू30 बजे भुसावल से चली लेकिन सामान्य रूप से पांच घंटे का यह सफर तय कर इटारसी पहुंचने में रात के 10 बज गए। इसी तरह प्रयागराज से पुणे के हडपसर जाने वाली स्पेशल ट्रेन (04107) बुधवार को सुबह 10रू20 बजे रवाना होनी थी लेकिन रात के 10 बजे जाने के बाद भी ट्रेन रवाना नहीं हो सकी थी। जंक्शन पर बार–बार एनाउंसमेंट कर ट्रेन के रात 10रू20 बजे जाने की सूचना दी जाती रही। इससे घंटों प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देरी का यह सिलसिला अन्य रूटों पर भी जारी है। चर्लापल्ली से प्रयागराज आने वाली चर्लापल्ली स्पेशल के भी पांच घंटे विलंब से पहुंचने की सूचना जंक्शन पर प्रसारित की गई। इसका निर्धारित समय बुधवार रात 10रू10 बजे कर दिया गया। इसके अलावा अयोध्या कैंट से लोकमान्य तिलक जाने वाली 01046 स्पेशल ट्रेन भी अपनी बदहाली की दास्तान बयां करती नजर आई। मंगलवार शाम 5रू05 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचने वाली यह ट्रेन बुधवार पूर्वाह्न 11रू50 बजे आई। हद तो तब हो गई जब यहां इसका ठहराव मात्र 10 मिनट का था, लेकिन ट्रेन डेढ़ घंटे तक प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी रही। यात्रियों का सवाल है कि आखिर रेलवे प्रशासन अतिरिक्त और महंगे किराये के नाम पर जेब काटने के बाद भी समयबद्धता की गारंटी क्यों नहीं दे पा रहा है। जंक्शन पर हडपसर स्पेशल जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्री अमित श्रीवास्तव ने बताया कि स्पेशल ट्रेनों की इस बेपटरी व्यवस्था ने रेलवे के दावों की पोल खोलकर रख दी है।

दूसरे जोनल रेलवे में ही स्पेशल ट्रेनें लेट हो जा रही हैं। एनसीआर जोन में स्पेशल ट्रेन समय में चलाना प्राथमिकता है। –डॉ. शिवम शर्मा, सीपीआरओ, एनसीआर

यूपीपीएससी: एलटी ग्रेड गणित का परिणाम जारी, खाली रह गए 385 पद

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की ओर से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक या प्रशिक्षित स्नातक) भर्ती–2025 के गणित विषय का परिणाम बुधवार देर शाम घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की ओर से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक या प्रशिक्षित स्नातक) भर्ती–2025 के गणित विषय का परिणाम बुधवार देर शाम घोषित कर दिया गया है।



आजम खां और अब्दुल्ला की जेल से हो सकती है रिहाई, जमानत मंजूर होने के बाद ईडी के वारंट पर टिकी निगाहें

प्रयागराज। दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों की सजा निलंबित करते हुए जमानत मंजूर कर ली है। जमानत की शर्तें और जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दोनों की रिहाई का रास्ता साफ हो हो गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकलपीठ ने दोनों की सजा निलंबित करने की अर्जियां मंजूर करते हुए जमानत दे दी। अदालत के इस आदेश के बाद दोनों की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।

हालांकि, रिहाई के लिए जमानत की शर्तों और आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अगर कोई वारंट नहीं जारी किया गया तो दोनों जेल से बाहर आ सकते हैं। आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम फिलहाल रामपुर जेल में बंद हैं। दोनों को दो पैन कार्ड रखने के मामले में सात–सात साल की सजा सुनाई गई थी।



क्या है दो पैन कार्ड मामला?

अभियोजन के अनुसार, यह मामला कथित तौर पर अलग–अलग जन्मतिथियों का उल्लेख करने वाले दूसरे पैन कार्ड को बनवाने और उसके इस्तेमाल से जुड़ा है। आरोपों में चुनावी नामांकन पत्रों में दूसरे पैन कार्ड का इस्तेमाल किए जाने का मामला भी शामिल है। आजम खां और अब्दुल्ला आजम ने निचली अदालत से मिली दोषसिद्धि और सजा को आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी है। इसी दौरान उन्होंने सजा निलंबित करने और जमानत देने की मांग की थी।

दोषसिद्धि पर रोक से अलग है सजा निलंबन

हाईकोर्ट से मिली राहत सजा निलंबित करने और जमानत देने से संबंधित है। इसे दोषसिद्धि पर रोक लगाए जाने के आदेश के समान नहीं माना जा सकता। पुनरीक्षण याचिकाओं पर अंतिम निर्णय होना अभी अलग न्यायिक प्रक्रिया है।

मकान के भीतर जमीन में गड़े तीन ड्रमों से मिले करोड़ों रुपये, करीब पांच करोड़ होने की आशंका

प्रयागराज। प्रयागराज के नवाबगंज क्षेत्र के बरईपुर रामनगर गांव में एक मकान के भीतर जमीन में गाड़े गए तीन ड्रमों से चार से पांच करोड़ रुपये मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। ड्रमों में पांच–पांच सौ रुपये के नोटों की गड्डियां मिलीं। इतनी बड़ी रकम कहां से आई और जमीन में क्यों छिपाई गई थी, पुलिस इसकी जांच कर रही है। मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है।

नवाबगंज के बरईपुर रामनगर गांव में बुधवार देर शाम एक मकान के भीतर जमीन में गड़े तीन ड्रमों से चार से पांच करोड़ रुपये मिले। इतनी बड़ी नकदी कहां से आई? इसे ड्रमों में भरकर जमीन में क्यों गाड़ा गया? पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है। मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है।

बुधवार देर शाम पुलिस को सूचना मिली कि बरईपुर रामनगर निवासी राकेश यादव के मकान में चोरी के रुपये जमीन में गाड़े गए हैं। सूचना पर एडीसीपी गंगापार पुष्कर वर्मा समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। तलाशी के दौरान पुलिस को जमीन गाड़े गए तीन ड्रम मिले। इसमें 500–500 नोटों की गड्डियां मिलीं। पुलिस ने आयकर समेत अन्य संबंधित विभागों को सूचना देते हुए रुपये सील कर दिए। बृहस्पतिवार को रुपयों की गिनती की जाएगी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि राकेश का भाई बबलू यादव पिछले कई वर्ष से पुणे में रहता था। वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में वह गांव आया था। उसके साथ दो जीजा और साढ़ू भी आए थे। चर्चा है कि रुपये वहीं से लाए गए थे। पुलिस इन सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।



परिवार में कुछ दिन पहले हुआ था विवाद

राकेश यादव के परिवार में कुछ दिन पहले विवाद होने की बात सामने आई है। पुलिस इस विवाद को भी जांच के दायरे में रखकर पड़ताल कर रही है। हालांकि, विवाद और गड़े मिले करोड़ों रुपये के बीच कोई संबंध है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस हिरासत में लिए गए राकेश यादव समेत चारों लोगों से पूछताछ कर रही है।

गांव में बनाई करोड़ों की संपत्ति

ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि राकेश यादव ने पिछले कुछ वर्षों में गांव में तेजी से संपत्ति बनाई। उसने कई बीघे खेत खरीदने के साथ करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से मकान बनवाया। इसके अलावा दो ट्रैक्टर और डीजे भी खरीदा। पुलिस संपत्ति जुटाने के स्रोत और नकदी के लेनदेन की पड़ताल कर रही है।

राकेश यादव के मकान के भीतर जमीन में गाड़े गए तीन ड्रमों से करोड़ों रुपये मिले। रुपये बरामद कर संबंधित विभाग को सूचना दे दी गई है। गिनती के बाद पता चलेगा कि कुल कितने रुपये हैं। रुपये कहां से आए, इसकी जांच की जा रही है। –सोनम कुमार, डीसीपी, गंगापार

जवाब की जगह पन्नों में दबे मिले नोट, अब सिस्टम से सवाल

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने उत्तर पुस्तिकाओं में 100 से 500 रुपये तक के नोट रखने वाले विद्यार्थियों की मानसिकता को समझने के लिए पहल की। जिन छात्र–छात्राओं की कॉपी में सवालों के जवाब की जगह पन्नों में नोट दबे मिले, उन्हें बोर्ड के क्षेत्रीय मुख्यालयों में बुलाकर इसका कारण पूछा गया। जवाब ऐसे–ऐसे मिले जो केवल ज्यादा अंक को बच्चों की प्रतिभा का पैमाना मान लेने वाली पूरी प्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश परीक्षार्थियों के मामले में संभवतरू देश का सबसे बड़ा राज्य शिक्षा बोर्ड है। इसमें 10वीं और 12वीं के 51 लाख से ज्यादा विद्यार्थी प्रति वर्ष परीक्षा देते हैं। तकनीक का सहारा लेकर विवाद रहित और नकल रहित परीक्षा कराने के लिए बोर्ड ने तमाम प्रयास किए। लेकिन, उत्तर पुस्तिकाओं में 50 से 500 रुपये तक के नोट मिलने का सिलसिला साल–दर–साल बढ़ता जा रहा है। आखिर बच्चों की इस मानसिकता के पीछे का सही कारण क्या है और उत्तरपुस्तिकाओं से रुपये निकलने के पीछे का मनोविज्ञान क्या है?

इसी को समझने के लिए यूपी बोर्ड के सचिव और प्रशासन के आला अफसरों ने सीधे उन विद्यार्थियों से बातचीत करने का फैसला किया, जिनकी कॉपी में नोट निकले थे। बोर्ड के नजदीकी क्षेत्रीय कार्यालयों में इन छात्र–छात्राओं को बुलाया गया। अधिकतर बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी पहुंचे। बोर्ड और विभाग के बड़े अफसरों के साथ जब बच्चे अकेले में मिले तो बड़ी रोचक जानकारियां सामने आईं।

लखनऊ से प्रयागराज आई एक छात्रा ने बताया कि उसने किसी भी उत्तर पुस्तिका में नोट नहीं रखा। उसने तो पूछताछ करने वालों को चुनौती दी कि सीसीटीवी की रिकार्डिंग देख लीजिए। इसके बाद उसे समझाकर वापस भेज दिया गया। सबसे रोचक वाक्या तो तब आया जब प्रदेश के एक क्षेत्रीय कार्यालय में आए विद्यार्थी ने कॉपी में नोट निकलने के सवाल पर साथ आए कक्ष निरीक्षक (अध्यापक) की ओर देखना शुरू कर दिया। शिक्षा अधिकारियों ने जब बच्चे पर जवाब के लिए जोर दिया तो कक्ष निरीक्षक खुद ही जवाब देने लगे। इसके बाद अभिभावक ने भी शिक्षकों की भूमिका पर सवाल उठाना शुरू कर दिया।

अभिभावकों के प्रश्न ज्यादा बड़े हैं...

प्रयागराज के क्षेत्रीय केंद्र में 23 जिलों के 87 विद्यार्थी जवाब देने के लिए बुलाए गए थे। उनके साथ आए अभिभावकों ने परीक्षा केंद्रों में नोट पहुंचने और कॉपी बिना चेक किए जमा कराने को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जो शिक्षक और कक्ष निरीक्षक विद्यार्थियों के दिमाग में यह बात बैठा रहे हैं कि ज्यादा नंबर पाने के लिए कॉपियों में नोट रखना चाहिए, उनकी पहचान की जानी चाहिए। उनका सवाल यह भी है कि जिन छात्रों को बुलाया गया है और कॉपी में नोट मिलने पर लिखित में जवाब लिया जा रहा है, उनके स्कूल–कॉलेजों में पढ़ाई के स्तर की भी पड़ताल होनी चाहिए। नकल रोकने के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे और कक्ष निरीक्षकों की सजग आंख परीक्षा कक्ष में नोटों की आमद नहीं रोक पा रही, तो इससे पूरी परीक्षा ही सवालों के घेरे में आ जा रही है।

सवाल पूरे सिस्टम से है...

वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में कॉपियों में नोट मिलने के करीब 400 मामले परीक्षकों ने पकड़े और ऊपर सूचित किया। न जाने कितने मामले ऐसे भी होंगे जो सूचित करने से रह गए होंगे। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि ज्यादा अंक पाने की होड़ ने परीक्षा प्रणाली को लचर किया है अथवा परीक्षा का उपहास बनाने के लिए यह खेल जान बूझकर किया जा रहा है।

इस मसले को केवल पूछताछ और बच्चों की सजा तक सीमित नहीं रखना चाहिए। चूंकि अभिभावकों की ओर से सवाल पूरे सिस्टम पर उठाया जा रहा है, इसलिए इसके पीछे की पूरी साजिश को बेनकाब करने की जरूरत है।

एमबीबीएस में दाखिला देने की मांग पर हस्तक्षेप से कोर्ट का इंकार

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर निवासी सुनने में दिव्यांग छात्रा काजल त्रिपाठी को दिव्यांगता आरक्षण के तहत एमबीबीएस में दाखिला देने की मांग पर हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर निवासी सुनने में दिव्यांग छात्रा काजल त्रिपाठी को दिव्यांगता आरक्षण के तहत एमबीबीएस में दाखिला देने की मांग पर हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा, न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि अपीलीय मेडिकल बोर्ड और केजीएमयू, लखनऊ की रिपोर्ट छात्रा के खिलाफ है। ऐसे में याचिका में हस्तक्षेप का आधार नहीं है। छात्रा ने नीट यूजी–2026 की परीक्षा दी थी। उसके यूडीआईडी प्रमाणपत्र में सुनने संबंधी स्थायी दिव्यांगता 40 प्रतिशत दर्ज थी। मेडिकल असेसमेंट बोर्ड ने दिव्यांगता 13.16 प्रतिशत आंकी, जबकि अपीलीय बोर्ड ने इसे 71.35 प्रतिशत बताया।

कफ सिरप मामले में महिला दवा कारोबारी की अंतरिम अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन कफ सिरप की तस्करी के मामले में आरोपी महिला कारोबारी को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही सरकार से दो हफ्ते में जवाबी हलफनामा तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन कफ



सिरप की तस्करी के मामले में आरोपी महिला कारोबारी को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही सरकार से दो हफ्ते में जवाबी हलफनामा तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला की एकल पीठ ने चंदौली निवासी महिला कारोबारी की अग्रिम जमानत याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची नवजात शिशु की देखभाल कर रही है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दवाओं की वैध खरीद–बिक्री से संबंधित दस्तावेज भी अर्जी के साथ दाखिल किए गए हैं। हालांकि, दस्तावेज के कूटरचित होने का आरोप अभी विवेचनाधीन है। लिहाजा, वह अग्रिम जमानत की हकदार है।

चार करोड़ रिकॉर्ड्स ऑनलाइन, दफ्तरों से हटा 200 टन कागज, महाप्रबंधक ने डॉक्यूमेंट्री को किया रिलीज

प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने बुधवार को डिजिटलीकरण की सफलता पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री का अनावरण किया। इसके तहत अब तक चार करोड़ से अधिक रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जा चुका है। उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने बुधवार को डिजिटलीकरण की सफलता पर



आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री का अनावरण किया। इसके तहत अब तक चार करोड़ से अधिक रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप में सुरक्षित किया जा चुका है।

डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से रेलवे में डिजिटल कार्यसंस्कृति को बढ़ावा देने, अभिलेखों के सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित संरक्षण तथा कागजी रिकॉर्ड पर निर्भरता कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान एनसीआर के दफ्तरों में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत 200 मीट्रिक टन कागज हटाया गया। इसके अतिरिक्त, पुराने रिकॉर्ड के निस्तारण से लगभग 25,000 वर्गफीट कार्यालयी स्थान खाली कराया गया है और डिजिटल अभिलेखों के संरक्षण के लिए 58 टेराबाइट से अधिक स्टोरेज क्षमता विकसित की गई है। डिजिटल रिकॉर्ड से आवश्यक दस्तावेज तक पहुंच आसान होने और उनके रखरखाव एवं खोज में लगने वाले समय की बचत होने में सहायता मिल रही है। महाप्रबंधक ने डिजिटलीकरण के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और शेष अभिलेखों को भी चरणबद्ध तरीके से डिजिटल करने पर जोर दिया।

अलीगढ़ और गाजियाबाद में भी रुकेगी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, रेलवे बोर्ड ने जारी की समय सारिणी

प्रयागराज। रेलवे बोर्ड ने वाराणसी से नई दिल्ली के बीच शुरू होने वाली स्लीपर वंदे भारत की समय सारिणी जारी कर दी है। इसका प्रयागराज और कानपुर के अलावा अलीगढ़ और गाजियाबाद में भी ठहराव रहेगा। ट्रेन के संचालन की तिथि का जल्द ही एलान होने की उम्मीद है। रेलवे बोर्ड ने वाराणसी से नई दिल्ली



के बीच शुरू होने वाली स्लीपर वंदे भारत की समय सारिणी जारी कर दी है। इसका प्रयागराज और कानपुर के अलावा अलीगढ़ और गाजियाबाद में भी ठहराव रहेगा। ट्रेन के संचालन की तिथि का जल्द ही एलान होने की उम्मीद है।

रेलवे बोर्ड के अनुसार, यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलाई जाएगी। वाराणसी से यह ट्रेन शुक्रवार को छोड़कर और नई दिल्ली से शनिवार को छोड़कर बाकी दिन चलेगी। नियमित ट्रेन के रूप में वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली गाड़ी (27421) रात 8रू50 बजे प्रस्थान करेगी और रात 10रू35–10रू40 बजे प्रयागराज, 12रू40–12रू45 बजे कानपुर सेंट्रल, रात 3रू55–3रू57 बजे अलीगढ़ जंक्शन, सुबह 5रू25–5रू27 बजे गाजियाबाद एवं 6रू10 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी।

वहीं वापसी में नई दिल्ली से वाराणसी आने वाली गाड़ी (27422) रात 9रू40 बजे चलकर रात 10रू13–10रू15 बजे गाजियाबाद, रात 11रू20–11रू22 बजे अलीगढ़, रात 2रू45–2रू50 बजे कानपुर सेंट्रल और सुबह 5रू05 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। पांच मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन वाराणसी पहुंचेगी। ट्रेन की अधिकृत समय सारिणी जारी होने की पुष्टि एनसीआर के सीपीआरओ डा. शिवम शर्मा ने की है। रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेलवे (नई दिल्ली) और उत्तर मध्य रेलवे (प्रयागराज) के महाप्रबंधकों को इस संबंध में पत्र भेजकर आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

सत्संग का प्रभाव, चेतना और विवेक का पर्याय हैः विनोदानन्द

जमुनापार महोत्सव के दूसरे दिन लोक कलाकारों ने बांधी समां

करछना। क्षेत्र के रामपुर स्थित श्री बृज मंगल सिंह इंटर कालेज में आयोजित 28वें जमुनापार महोत्सव के दूसरे दिन मंच पर पहुंचे रामकथा प्रवाचकों ने मानस ज्ञान गंगा प्रवाहित कर श्रोताओं मंत्रमुग्ध कर दिया।इस दौरान,विनु सत्संग विवेक न होई,जैसी चौपाइयों की मार्मिक व्याख्या करते हुए कथा वाचक स्वामी विनोदानन्द सरस्वती जी महाराज ने कहा कि मनुष्य में यही सत्संग का प्रभाव सत्यभाव का निरुपण करते हुए चेतना और विवेक का पर्याय बन जाता है। मिर्जापुर से पधारे आचार्य पंकज



जी महाराज ने भरत महिमा का बखान कर भक्तगणों को भाव विभोर कर दिया। इसके पूर्व लोकरंग कार्यक्रम में जमुनापार के लोक कलाकारों ने पारम्परिक लोकगीतों की प्रस्तुति से खूब तालियां बटोरी। बबलू दीवाना, अशोक कुशवाहा, रणजीत, रामानन्द और पवन प्रेमी ने सोहर, दादरा, नकटा, घाटोगीत पर खूब तालियां बटोरी। वहीं मोनू मस्ताना,गजराज सिंह, भोला सिंह दीवाना, शनि विश्वकर्मा, रंजीत और इन्द्रजीत यादव ने कजरी, खेमका, मुंडन गीतों पर खूब समां बांधी। प्रधानाचार्य मनीष तिवारी ने सभी श्रोताओं के प्रति आभार प्रकट किया। मंच का संचालन डा. के.के.त्रिपाठी ने किया। इस मौके पर डॉ. दिनेश सोनी, रामबाबू यादव पंचमलाल यादव, कमलेश यादव, विश्वेष ओझा, राजनारायण जौहरी, हनुमान, कल्लू प्रधान,रमेश तिवारी, राजकुमार विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे।

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में विधानसभा चुनाव का रोडमैप तैयार होगा

लखनऊ, संवाददाता। भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में कल सरकार और संगठन की एकजुटता का संदेश दिया जाएगा। आमतौर पर संगठन सरकार से बड़ा होता है कहने वाले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश कार्यसमिति में योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रशंसा करेंगे वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक केशव के बातों का अनुमोदन करेंगे। बृहस्पतिवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश कार्यसमिति के एजेंडे को अंतिम रूप दिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश पदाधिकारी बैठक में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने प्रदेश कार्यसमिति बैठक के कार्यक्रम की जानकारी दी। धर्मपाल सिंह ने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह सुबह 10 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। वहां सीएम योगी आदित्यनाथ, पंकज चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित सरकार के मंत्री और पार्टी पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे। सुबह 10.30 बजे से बीबीएयू के सभागार में कार्यसमिति बैठक शुरू होगी। उद्घाटन सत्र को गृहमंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद राजनीतिक सत्र होगा, इसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य राजनीतिक प्रस्ताव पेश करेंगे। राजनीतिक प्रस्ताव में केंद्र की मोदी सरकार के 12 साल और प्रदेश की योगी सरकार के साढ़े नौ साल की उपलब्धियां, 2017 से पहले और उसके बाद यूपी में आए बदलाव सहित अन्य उपलब्धियां शामि होंगी। उसके बाद आगामी कार्ययोजना पर सत्र होगा। प्रदेश महामंत्री अभिजात मिश्रा विधानसभा चुनाव से पहले तक पार्टी के कार्यक्रमों और अभियानों के बारे में जानकारी देंगे। पार्टी किस तरह आगामी दो महीने तक किसी न किसी कार्यक्रम के जरिए जनता के बीच जाकर अपनी संपर्क और संवाद स्थापित करेगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने कार्यसमिति की व्यवस्थाओं में लगाए गए पदाधिकारियों से अब तक की तैयारी की समीक्षा की। धर्मपाल सिंह ने बताया कि समापन सत्र को सीएम योगी संबोधित करेंगे। सीएम आगामी चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं से दिनरात चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान करेंगे। धर्मपाल सिंह ने बताया कि भाजपा के जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों, क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक 30 अक्टूबर को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में होगी। गृहमंत्री अमित शाह दोपहर 2 बजे वापस दिल्ली के लिए लौट जाएंगे। इस बीच वे लंच के दौरान सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से आगामी चुनावों की तैयारी पर चर्चा करेंगे।

बिजली कनेक्शन के नाम पर रिश्वत मांगने पर सस्पेंड होगा अधिकारी

मंत्री ने सुनीं पेयजल, अतिक्रमण, विद्युत कनेक्शन और बिल सुधार से जुड़ी समस्याये

लखनऊ, संवाददाता। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आज अपने आवास पर जनसुनवाई कर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में पेयजल, अतिक्रमण, विद्युत कनेक्शन, विद्युत बिल में सुधार और नए विद्युत सबस्टेशन की स्थापना सहित नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग से संबंधित विभिन्न समस्याएं सामने आईं। श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाए। जनसुनवाई के दौरान लखनऊ निवासी विद्युत उपभोक्ता अभिनव त्रिपाठी ने अपने घरेलू विद्युत कनेक्शन से संबंधित शिकायत रखते हुए आरोप लगाया कि फरवरी में 3 किलोवाट के घरेलू विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। विभाग द्वारा 1 मार्च को जारी 11,622 रुपये का स्टीमेट उन्होंने जमा भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कनेक्शन नहीं दिया गया। उपभोक्ता ने आरोप लगाया कि बाद में संबंधित सहायक अभियंता शुभम सिंह द्वारा कनेक्शन देने के एवज में 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी गई। रिश्वत नहीं देने पर 12 अक्टूबर को लगभग 2.24 लाख रुपये का नया स्टीमेट जारी कर दिया गया। ऊर्जा मंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को तत्काल जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाए और यदि अधिकारी दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल सस्पेंड की कार्रवाई की जाए।

परंपरा, संस्कृति, आदर्श, विश्वास एवं समर्पण का अनूठा संगम करवाचौथ मेहंदी उत्सव सम्पन्न

संगम करवाचौथ मेहंदी उत्सव का आयोजन अग्रवाल सभा महिला वाहिनी, प्रयागराज के द्वारा किया गया



प्रयागराज। जनपद में दिन बुधवार को अग्रवाल सभा महिला वाहिनी, प्रयागराज के द्वारापरंपरा, संस्कृति, आदर्श, विश्वास एवं समर्पण का अनूठा संगम करवाचौथ मेहंदी उत्सव संगम करवाचौथ मेहंदी उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रीमती रोली अग्रवाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि।भारतीय संस्कृति केवल हमारे रीति–रिवाजों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारी परंपराओं, संस्कारों, पारिवारिक मूल्यों, आपसी प्रेम और अटूट विश्वास की अमूल्य धरोहर है। हमारे प्रत्येक त्योहार में कोई न कोई सुंदर संदेश छिपा होता है, जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और रिश्तों की मिठास को और गहरा बनाता है।करवाचौथ का पर्व प्रेम, विश्वास, समर्पण और वैवाहिक जीवन की मधुर भावनाओं का प्रतीक है। इस पावन अवसर डॉ. दिव्या अग्रवाल ने भी अपने विचार साझा करते हुए कहा कि पर हाथों में रचती मेहंदी केवल सोलह श्रृंगार का हिस्सा नहीं, बल्कि भारतीय नारी की सुंदरता, उमंग, उल्लास और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है।इन्हीं भावनाओं को आत्मसात करते हुए अग्रवाल सभा महिला वाहिनी, प्रयागराज द्वारा करवाचौथ मेहंदी उत्सव का आयोजन अग्रसेन भवन, प्रयागराज में किया।श्रीमती रंजना अग्रवाल ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य केवल एक उत्सव मनाना नहीं, बल्कि समाज की मातृशक्ति को एक ऐसा स्नेहपूर्ण मंच प्रदान करना है, जहाँ महिलाएँ अपनी परंपराओं से जुड़ें, आपसी संबंधों को प्रगाढ़ बनाएँ और एक–दूसरे के साथ प्रेम, सम्मान एवं आत्मीयता के भाव साझा करें। तत्पश्चात श्रीमती शिल्पी जैन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि। हमारा विश्वास है कि जब महिलाएँ एकजुट होती हैं, तो परिवार मजबूत होते हैं, समाज में सकारात्मकता आती है और संस्कृति की जड़ें और गहरी होती हैं। महिला वाहिनी का प्रयास है कि सामाजिक आयोजनों के माध्यम से हमारी भावी पीढ़ी भी अपनी गौरवशाली परंपराओं, संस्कारों और आदर्शों से परिचित हो तथा उन्हें आगे बढ़ाने का संकल्प ले।हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, हमारी परंपराएँ हमारी धरोहर हैं और हमारी एकता हमारी शक्ति है। आइए, इस करवाचौथ मेहंदी उत्सव के माध्यम से प्रेम, विश्वास, सौहार्द और सामाजिक एकता के रंगों को और गहरा करें। मिलकर ऐसा वातावरण बनाएँ, जहाँ हर महिला को सम्मान मिले, हर रिश्ते में आत्मीयता हो और हर आयोजन समाज को जोड़ने का माध्यम बने। आप सभी मातृशक्ति का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में करियर काउंसलिंग एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित

प्रयागराज, करछना। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, करछना में प्रगति ग्रामोद्योग एवं समाज कल्याण संस्थान, प्रयागराज की



ओर से करियर काउंसलिंग, आत्मरक्षा एवं बालिका सुरक्षा विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में करछना थाने के बाल संरक्षण अधिकारी, उनकी सहायक सहित पुलिसकर्मी, संस्था के प्रतिनिधि संजय जायसवाल एवं अब्दुल रहमान तथा विद्यालय के समस्त स्टाफ की सहभागिता रही।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को बालिका सुरक्षा, आत्मरक्षा, साइबर अपराध से बचाव और करियर निर्माण के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। उन्हें सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने तथा किसी भी आपात स्थिति में सहायता प्राप्त करने के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूक किया गया।

छात्राओं ने खुलकर साझा कीं अपनी समस्याएं,प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं ने अपनी सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और आशंकाओं को साझा किया। उन्होंने छेड़खानी, यातायात के दौरान असुरक्षा तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी तस्वीरें अपलोड होने के डर जैसी चिंताओं को सामने रखा। इसके साथ ही छात्राओं ने अपने भविष्य और करियर को लेकर सवाल पूछे तथा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के उपायों पर चर्चा की।लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करने के लिए किया प्रेरित,करियर काउंसलिंग के दौरान छात्राओं को नियमित रूप से पढ़ाई करने, अपने लक्ष्य निर्धारित करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें बताया गया कि 12वीं कक्षा तक मन लगाकर पढ़ाई करने से उच्च शिक्षा और करियर के विभिन्न विकल्पों को समझने में मदद मिलती है।

साथ ही, मोबाइल फोन और इंटरनेट का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए न करके पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और करियर संबंधी जानकारी प्राप्त करने में करने की सलाह दी गई।कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, साइबर अपराधों से बचाव के उपाय बताना तथा उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना रहा। इस पहल के माध्यम से छात्राओं को अपनी समस्याएं खुलकर रखने, सवाल पूछने और अपने भविष्य के प्रति जागरूक होकर आगे बढ़ने का अवसर मिला।

एमएलसी चुनावः नतीजों ने दी बीजेपी को टेंशन, सपा को ऑक्सीजन

गोरखपुर से आगरा तक भाजपा को भितरघात को चोट,सपा ने उम्मीदवार तय करने में नही लगाई थी देरी

लखनऊ, संवाददाता। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों के नतीजों ने भाजपा की चुनौती बढ़ा दी है।वही समाजवादी पार्टी के लिए संजीवनी से कम नही है एमएलसी चुनाव। पार्टी भले ही दोबारा छह सीटें हासिल करने में सफल रही हो लेकिन सपा की सीटों में बढ़ोत्तरी से भगवा खेमे पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी ने नेता विरोधी दल का ओहदा ही नही बरकरार रखा बल्कि अपनी परिषद में संख्या बल दुरूस्त कर लिया है।बीजेपी को विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतिक मोर्चे पर अब और अधिक सतर्क होना पड़ेगा। खुद सीएम योगी के चुनाव की कमान संभालने और आठ जनसभाओं के बाद ही इस हालत के पीछे कई कारण मानें जा रहे हैं। गोरखपुर से आगरा तक भितरघात दिखाई दिया है। छह सीटों पर देरी से टिकट घोषित करना भी भाजपा को भारी पड़ गया है। इन छह में से चार सीटें पार्टी हार गई जबकि महीनों पहले घोषित पांच प्रत्याशियों में से चार ने जीत हासिल कर ली। 11 सीटों के लिए चुनाव हुए, भाजपा के पास छह सीटें थीं। इस बार भी पार्टी के खाते में उतनी ही सीटें आई हैं। लखनऊ की जीती हुई स्नातक सीट भाजपा इस बार हार गई। बीजेपी ने लखनऊ की शिक्षक सीट से उमेश द्विवेदी और स्नातक सीट पर अवनीश पटेल, बरेली–मुरादाबाद शिक्षक सीट पर डा. हरी सिंह ढिल्लो, मेरठ शिक्षक सीट पर श्रीचंद शर्मा, आगरा–अलीगढ़ स्नातक सीट पर मानवेंद्र प्रताप सिंह को 24 मई को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। यह सभी सिटिंग एमएलसी थे और उन्होंने वोट बनवाने के लिए पर्याप्त मेहनत की थी। इन पांचों में सिर्फ अवनीश पटेल को सफलता नहीं मिल सकी। छह सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान बीते 29 सितंबर को किया जबकि 23



अक्तूबर को मतदान होना था। मेरठ स्नातक सीट से दिनेश गोयल भाजपा और गोरखपुर–फैजाबाद शिक्षक सीट पर ध्रुव कुमार त्रिपाठी शिक्षक दल शर्मा गुट के सिटिंग एमएलसी थे। यही दोनों जीत पाए। बाकी आगरा शिक्षक सीट से हरी किशोर तिवारी, वाराणसी स्नातक सीट से केदार नाथ सिंह और वाराणसी शिक्षक सीट से प्रमोद कुमार मिश्रा, इलाहाबाद–झांसी स्नातक सीट से अशोक कुमार राठौर को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। भाजपा को भितरघात झेलना पड़ा। यह सिलसिला आगरा सीट से लेकर प्रयागराज, लखनऊ और गोरखपुर तक देखने को मिला। प्रतापगढ़ में पार्टी के स्थानीय संगठन ने एक पूर्व मंत्री द्वारा विरोधियों की मदद करने की शिकायत की। आगरा सीट पर भाजपा से जुड़े कई वित्तविहीन स्कूल संचालकों ने भी सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल का साथ दिया। चुनाव से ठीक पहले भाजपाई से सपाई हुए संजयन त्रिपाठी और बागी तेवर दिखाने वाले भाजपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी पार्टी को झटका दिया। भाजपा के ध्रुव त्रिपाठी की जीत का अंतर घटा दिया।

अँजुरी भरे उजास

(छप्पय)

कहे अमा की रात प्रकृति के प्रिय साथी से।
तारक दल–सा आज दीप आए माटी से।
अँजुरी भरे उजास ओढ़कर प्रेम दुशाला।
चटक यामिनी बीच पी रहे तम का प्याला।
मौन साधना ज्योति की, उर्जित कर संसार को।
चिंतन को शुभ राह दे भरती विमल विचार को।।

धूमिल–धूमिल चाँद सितारे हुए नदारद।
देख अमा की रात दीप बन गए सभासद।
तिमिर नाशिनी ज्योति जगत को राह दिखाती।
हरकर सभी विशाद अहं का सच दिखलाती।
माटी का छोटा दिया मिटा रहा जग का तमस।
जलकर खुद ही दे रहा जीवन को नव रस सरस।।

डॉ. प्रदीप चित्रांशी
लूकरगंज, प्रयागराज

मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता व्याख्यान का आयोजन

प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध सीएमपी डिग्री कॉलेज में मनोविज्ञान विभाग के हैप्पीनेस लैब कोर्स के तत्वाधान में एक 'मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता' व्याख्यान सीरीज का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर नेहा आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर महाविद्यालय गुलाब देवी महिला पीजी कॉलेज बलिया संबंध जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया ने मानसिक स्वास्थ्य विषय पर अपने विचार रखें। उन्होंने छात्र–छात्राओं को अवगत कराया की मानसिक स्वास्थ्य को



बेहतर बनाना वर्तमान समय की प्राथमिक आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति छात्र–छात्राओं को जागरूक किया। व्याख्यान के अंतर्गत वास्तविक प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए छात्र–छात्राओं को विभिन्न रणनीतियों का अभ्यास कराया गया,तथा सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। संपूर्ण का कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन कार्यक्रम समन्वयक डॉ रंजना तिवारी,समन्वयक हैप्पीनेस लैब कोर्स द्वारा किया गया। सभी छात्र–छात्राएं इस व्याख्यान सीरीज से काफी लाभान्वित हुए।

उत्तर मध्य रेलवे

निविदा सूचना संख्याः 25-विद्युत/सा0/प्रयागराज/26-27 दिनांकः 20.10.2026

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (सामान्य) उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज निर्धारित प्रपत्र पर निम्नलिखित कार्यों हेतु ई-निविदा दिनांक 20.11.2026 समय 15:00 बजे तक आमंत्रित करते हैं निविदा सम्बंधित विस्तृत विवरण निम्नलिखित है-

निविदा सूचना संख्याः ELG-58-2627	कार्य की लागत (₹ में): 14536455.58
बिड सिक्योरिटी (₹ में): 290700.00	
कार्य का नामः CNBN (न्यू कानपुर) में रनिंग रूम को सुसज्जित करने" के संबंध में एयर कंडीशनिंग (AC) की व्यवस्था और बिजली आपूर्ति बढ़ाने का कार्य।	
निविदा सूचना संख्याः ELG-59-2627	कार्य की लागत (₹ में): 28068017.85
बिड सिक्योरिटी (₹ में): 561800.00	
कार्य का नामः रेलवे लोको रनिंग स्टाफ के लिए MODTI/CNB में 400 बिस्तरों की क्षमता वाले होस्टल भवन के निर्माण" के संबंध में एयर कंडीशनिंग (AC) की व्यवस्था और बिजली आपूर्ति बढ़ाने का कार्य।	
निविदा सूचना संख्याः ELG-60-2627	कार्य की लागत (₹ में): 6653445.85
बिड सिक्योरिटी (₹ में): 133100.00	
कार्य का नामः गोविन्दपुरी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में सुधार से संबंधित विद्युत कार्य। प्रयागराज मंडल के पनकी धाम (PNKD) स्टेशन पर, ADEN/LICNB के अंतर्गत प्लेटफार्म 2/3 में सुधार/अपग्रेडेशन का कार्य।	
निविदा सूचना संख्याः ELG-61-2627	कार्य की लागत (₹ में): 12650714.16
बिड सिक्योरिटी (₹ में): 253000.00	
कार्य का नामः ADEN/HQ-II/CNB के अंतर्गत, फतेहगंज में छोड़े गए क्वार्टरों के स्थान पर 12 यूनिट टाइप-III (G+2) क्वार्टरों का निर्माण तथा इसके लिए बाहरी विद्युत कार्य और बिजली आपूर्ति में वृद्धि। ADEN/HQ-II/CNB के अंतर्गत, गोविंद नगर कॉलोनी में छोड़े गए टाइप-II और टाइप-III क्वार्टरों के स्थान पर 12 यूनिट टाइप-III (G+2) क्वार्टरों का निर्माण। ADEN/HQ-II/CNB के अंतर्गत, गोविंद नगर कॉलोनी में छोड़े गए टाइप-II क्वार्टरों के स्थान पर 15 यूनिट टाइप-II (G+2) क्वार्टरों का निर्माण। ADEN/HQ-II/CNB के अंतर्गत, तेजस मिल में छोड़े गए क्वार्टरों के स्थान पर 15 यूनिट टाइप-II (G+2) क्वार्टरों का निर्माण। ADEN/HQ/CNB के अंतर्गत, गोविंद नगर रेलवे कॉलोनी में 15 यूनिट टाइप-II क्वार्टरों का निर्माण।	
निविदा सूचना संख्याः ELG-62-2627	कार्य की लागत (₹ में): 9624808.66
बिड सिक्योरिटी (₹ में): 192500.00	
कार्य का नामः "प्रयागराज डिपो में पुरानी CDO बिल्डिंग के पुनर्वास द्वारा एक उपयुक्त प्रशासनिक सुविधा के निर्माण" के लिए बाहरी विद्युत कार्य और बिजली आपूर्ति में वृद्धि। प्रयागराज स्थित नवीनीकृत लोनी को तिनन स्टोर में बदलना"।	

कार्य समाप्त करने की समयावधिः 12 महीने। निविदा खोलने की तिथिः 20.11.2026, समयः 15:00 बजे।

इसे सक्षम के DEE(G)PRYJ का अनुमोदन प्राप्त है। नोटः 1. उपरोक्त ई-टेंडर के साथ पूरी जानकारी (निविदा दस्तावेज के साथ) वेबसाइट www.ireps.gov.in पर 15:00 बजे निविदा खोलने की तिथि तक उपलब्ध है। 2465/26(AK)

North central railways @CPRONCR www.ncr.indianrailways.gov.in

उत्तर मध्य रेलवे

सं0 सीएम-1/एम.यू.टी. एस. सहायक/पार्ट-1/प्रयागराज/2026 दिनांक: 27.10.2026

सूचना

यह आवेदन नौकरी हेतु नहीं है।

।यह नियुक्ति पूरी तरह से संविदात्मक है और इसमें कोई सुविधाएँ जैसे रेलवे सेवा में अवशोषण, सेवा का नियमितीकरण, बोनस, रेलवे पास सुविधाएँ आदि नहीं हैं)।

उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, भारत के राष्ट्रपति की ओर से, सामान्य नागरिक और सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों से बन्द टिकटों में प्रयागराज मंडल के प्रयागराज, प्रयागराज छिवकी, कानपुर सेंट्रल एवं अलीगढ़ स्टेशन पर 'अनारक्षित' टिकट जारी करने के लिए 'M-UTS' (मोबाइल-अन-रिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम) सहायक के रूप में पायलट आधार पर काम करने के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। स्टेशनों के नाम और ब्रेक्ष विवरण निम्न है-

स्टेशन का नाम	स्टेशन कोड	स्टेशन कटेगरी	नियुक्त किए जाने वाले सहायकों की संख्या	कार्य की अवधि
प्रयागराज	PRYJ	NSG-2	36	30.06.2027 तक
प्रयागराज छिवकी	PCOI	NSG-2	12	
कानपुर सेंट्रल	CNB	NSG-2	36	
अलीगढ़	ALJN	NSG-3	18	

जमानत राशि (₹): 10,000/- आवेदन शुल्क (₹): 500/-

1. सभी सम्बन्धित नियमों एवं शर्तों के साथ आवेदन (अधिसूचना की तिथि से प्रारम्भ होकर) दिनांक 26.11.2026 को 11:00 बजे तक उपलब्ध हैं। आवेदन पत्रों किसी भी कार्य दिवस (सोमवार से शनिवार तक) समय 09:00 बजे से 17:00 बजे तक प्रयागराज, प्रयागराज छिवकी, कानपुर सेंट्रल एवं अलीगढ़ के बुकिंग कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्रों का मूल्य ₹ 500 /- रुपये (अप्रतिदेय) है, जिसे बुकिंग कार्यालय में जमा करना होगा और मूल एम0आर0 वाले आवेदन फार्म के साथ नत्थी करना होगा। 2. आवेदन फार्म उत्तर मध्य रेलवे के वेबसाइट www.ncr.indianrailways.gov.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। आवेदन फार्म का मूल्य ₹500/- है। आवेदक को आवेदन के साथ किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा वरिष्ठ मण्डल वित्त प्रबन्धक, उम्0रे0, प्रयागराज, के पक्ष में जारी ₹ 500/- का बैंक ड्राफ्ट/डीडी0 डाउनलोड आवेदन पत्रों के मूल्य के रूप में संलग्न करना होगा। 3. निर्धारित पूर्णतः भरे हुए तथा सभी औपचारिकताओं के साथ पूर्ण आवेदन पत्रों बन्द लिफाफे में वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक, वाणिज्य शाखा, द्वितीय तल, मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय, उत्तर मध्य रेलवे, नवाब युसुफ रोड, प्रयागराज के कार्यालय में रखे बॉक्स में तथा उप मुख्य यातायात प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे स्टेशन भवन, कानपुर सेन्ट्रल के कार्यालय में रखे बॉक्स में दिनांक 26.11.2026 को 13:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे और उन्हें उसी दिन 15:30 बजे खोला जाएगा। यदि किसी कारण से उक्त तिथि को अवकाश घोषित कर दिया जाता है, तो अगले कार्य दिवस में उसी स्थान और समय पर आवेदन खोले जायेंगे। 4.विलम्ब से प्राप्त आवेदन न तो स्वीकार किए जायेंगे और न उन पर विचार किया जायेगा तथा अधूरे/ गलत भरे हुये फार्म अस्वीकार/निरस्त कर दिये जायेंगे। 5. रेल प्रशासन किसी भी आवेदन को किन्हीं भी परिस्थितियों में स्वीकार/अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। सहायक वाणिज्य प्रबन्धक/कोचिंग उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज 2457/26(AK)

North central railways @CPRONCR www.ncr.indianrailways.gov.in

सम्पादकीय.....

स्रोत हो सुरक्षित

पत्रकारिता के पेशे में मीडियाकर्मी का नैतिक दायित्व होता है कि वह किसी खोजपूर्ण खबर में सहायक स्रोत की सुरक्षा और विश्वास को कायम रख सके। अपने गोपनीय स्रोत की सुरक्षा का वायदा सुनिश्चित करना महज एक पेशेवर शिष्टाचार नहीं है, सही मायने में यह खोजी पत्रकारिता की बुनियाद भी है। यदि जनहित के लिए महत्वपूर्ण गोपनीय सूचना देने वाले का भरोसा खत्म होगा तो भ्रष्टाचार और जन–विरोधी कार्यों में लिप्त लोगों के गलत कार्यों का खुलासा करने वाले लोग आगे नहीं आएंगे। यानी व्हिसलब्लोअर किसी गंभीर कदाचार आदि के मुद्दे पर चुप्पी साध सकते हैं। यदि सूचना स्रोत की गोपनीयता भंग होती है, तो गलत कामों के वास्तविक तथ्य कभी भी सामने नहीं आ पाएंगे। बहुत संभव है कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र के हित में, जनता को जानने योग्य जरूरी जानकारी से वंचित होना पड़ सकता है। इस विषय के महत्व की गंभीरता के चलते ही देश के सर्वोच्च न्यायालय में देश के 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट' यानी डीपीडीपी को चुनौती दी गई। जिसने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सार्वजनिक विमर्श में ला दिया है। यही वजह है कि डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन ने चेताया है कि इस कानून के प्रावधान किसी मीडियाकर्मी के गोपनीय स्रोतों को सार्वजनिक कर सकते हैं। जो स्वतंत्र समाचार संग्रहण और इस बाबत जांच–पड़ताल में बाधक साबित हो सकते हैं। इस समस्या का चिंताजनक पहलू यह भी कि सरकार के पास नागरिकों की निजी सूचना एकत्र करने वाली संस्थाओं से जानकारी हासिल करने के अधिकार हैं। जिससे उन लोगों की पहचान उजागर हो सकती है जो भरोसे के चलते ही पत्रकारों के पास आते हैं। निश्चय ही किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी बंदिशें लादने से मीडिया की स्वतंत्रता पर आंच आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद, कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बाबत जवाब मांगा है। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 17 नवंबर तय की है। इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि आज की तेजी से डिजिटल होती दुनिया में निजता की सुरक्षा बनाये रखना बहुत आवश्यक है। निस्संदेह, नागरिकों को उनकी निजी जानकारी का दुरुपयोग होने से बचाया जाना बेहद जरूरी है। साथ ही यह भी जरूरी है कि निजता की सुरक्षा के लिये बनाया गया कोई कानून प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ताधीशों के लिये ऐसा जरिया नहीं बन जाना चाहिए, जो तथ्यों की तलाश व जांच–पड़ताल में बाधक बने। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि शासन–प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और कॉर्पोरेट में होने वाली गड़बड़ियों की पड़ताल अकसर ऐसे लोगों पर निर्भर करती है, जो बड़े निजी जोखिम को उठाकर भी वास्तविक तथ्य देश व समाज हित में बताने को राजी होते हैं। ऐसे में यदि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना उनकी पहचान उजागर हो जाती है तो पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर इसका व्यापक प्रतिकूल असर पड़ सकता है। फिर जोखिम उठाकर सूचना देने वाले लोग, ऐसा करने से कतराने लगते हैं। इससे जुड़ा एक वास्तविक पहलू यह भी है कि अपने स्रोत की सुरक्षा का अधिकार पत्रकारों को बिना किसी जवाबदेही के काम करने की छूट नहीं देता है। लेकिन यदि कोई अपवाद सामने आता है तो उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। उसका सार्वजनिक होना बेहद जरूरी है। वहीं उसकी स्वतंत्र न्यायिक निगरानी होनी चाहिए। ऐसे में न्यूजरूम के रिकॉर्ड तक बिना किसी रोक–टोक के पहुंच होने से, स्रोत की सुरक्षा और जनता के जानने के अधिकार को नुकसान पहुंच सकता है। देश की शीर्ष अदालत से उम्मीद की जाती है कि बहुत सावधानी से निजता और प्रेस की आजादी के बीच संतुलन बनाया जाए। यदि वास्तविक पत्रकारिता के कार्यों के लिये स्पष्ट छूट दी जाती है, और साथ ही गोपनीय स्रोत के उजागर होने से रोकने के लिये सुरक्षा उपाय भी हों, तो इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कानून जनहित से जुड़ी रिपोर्टिंग में बाधा न बनेगा।

स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए एक और चुनौती

डॉ. दीपक पाचपोर

केंद्र को अब पारदर्शी चुनावी फंडिंग प्रणाली पर काम करना चाहिएसर्वोच्च न्यायालय को बधाई चुनावी बांड रद्द करने के आदेश से लोकतंत्र मजबूत हुआ

मोदी सरकार के 12 वर्षों में भारत में प्रेस की आजादी काफी ज्यादा खतरे में पड़ चुकी है। कार्पोरेट पूंजी ने स्वतंत्र पत्रकारिता पर कई तरह की बेड़ियां लगा ही दी हैं, ऊपर से सरकार के रवैये ने भी निर्भीक, स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता को काफी नुकसान पहुंचाया है। सरकार ने निजता की सुरक्षा के नाम पर जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण का कानून बनाया है, वह भी अब पत्रकारिता की राह में बड़ा रोड़ा बन रहा है। इस बाधा को दूर करने के लिए डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। डीएनपीए की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। गौरतलब है कि डीएनपीए के माध्यम से 21 समाचार प्रकाशकों ने कानून के प्रावधानों को चुनौती दी है। जिनमें वे मीडिया संस्थान भी शामिल हैं, जिनके मालिकाना हक गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के पास हैं। मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने डीएनपीए की याचिका पर सुनवाई की और केंद्र सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख दी है। हालांकि केंद्र सरकार को नोटिस जारी होने का अर्थ यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कानून की वैधता और उसके प्रावधानों पर अंतिम निर्णय होना बाकी है और यहीं सारा पेंच फंसा हुआ है। क्योंकि अगर अदालत का फैसला कानून निरस्त करने या इसमें प्रावधानों में संशोधनों वाला हुआ, तब तो खोजी पत्रकारिता के लिए उम्मीद बची रहेगी। वर्ना फिर बड़े घोटालों की पोल खोलने वाली खबरें बनाने का जोखिम भरा काम शायद ही हो पाए। ध्यान रहे कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 भारत का पहला व्यापक डेटा संरक्षण कानून है, जिसे 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। इस कानून का मकसद नागरिकों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा डेटा के वैध उपयोग के बीच संतुलन बनाना। केंद्र सरकार ने इससे संबंधित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025, पिछले साल 14 नवंबर को अधिसूचित किए हैं। नियमों का उल्लंघन करने या डेटा सुरक्षा में चूक होने पर श्डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड्य द्वारा 250 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। तकनीकी विकास के इस वक्त में डेटा लीक होने और व्यक्तिगत जानकारियां गलत हाथों में पड़ने के खतरे वाकई बहुत बढ़ चुके हैं। इस लिहाज से निजता की सुरक्षा के प्रावधान करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसकी आड़ में गलत बातों पर पर्दा डालने और उन खबरों को बाहर आने से रोकने की चालाकी हो, तो फिर सवाल उठने जायज हैं। मीडिया संगठनों का कहना है कि इस कानून के प्रावधान खोजी पत्रकारिता को बाधित कर सकते हैं, सूचना पाने के मौलिक अधिकार को प्रभावित कर सकते हैं और पत्रकारों के गोपनीय सूत्रों की पहचान उजागर होने का खतरा पैदा कर सकते हैं। मीडिया संगठनों की चिंता है कि व्यक्तिगत डिजिटल डेटा की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम यदि पत्रकारिता पर भी उसी तरह लागू होते हैं, तो भ्रष्टाचार, कॉरपोरेट अनियमितताओं, चुनावी गड़बड़ियों और सरकारी कामकाज की जांच करना मुश्किल हो सकता है। डीएनपीए की दलील है कि कानून के नोटिस और सहमति से जुड़े प्रावधानों को पत्रकारिता पर लागू करने से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में उसकी निजी जानकारी जुटाने या उसकी गतिविधियों की जांच करने से पहले पत्रकारों को उसे सूचना देनी पड़े या उसकी सहमति लेनी पड़े। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं या कोई खोजी पत्रकार किसी के भ्रष्ट कामों का पता लगा भी ले, तो भी उसे उजागर करने से पहले उसे संबंधित व्यक्ति को ही सूचना देनी होगी। और जाहिर है कि उसके बाद वह उस खबर को शायद ही सामने ला पाए, क्योंकि फिर उस खोजी पत्रकार पर व्यक्तिगत डेटा मिटाने के अधिकार का इस्तेमाल खबर को दबाने या उनमें बदलाव कराने की मांग के लिए किया जा सकता है। मीडिया समूहों की आपत्ति का मूल सवाल यह है कि व्यक्तिगत निजता की रक्षा और स्वतंत्र पत्रकारिता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। उनका कहना है कि निजता की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन ऐसे नियमों से पत्रकारों की जनहित में जानकारी जुटाने और प्रकाशित करने की क्षमता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। रिपोर्टों के मुताबिक, मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच अगस्त में हुई बैठक में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा को लेकर आश्वासन दिया गया था। लेकिन डीएनपीए का कहना है कि पत्रकारों के लिए कानून में स्पष्ट लिखित छूट नहीं होने से उसकी चिंताएं दूर नहीं हुई हैं। एसोसिएशन ने इस मुद्दे को केवल तकनीकी या डेटा प्रबंधन से जुड़ा विवाद नहीं माना है। उसके मुताबिक, कानून के कुछ प्रावधानों का असर यह हो सकता है कि समाचार संस्थान जनहित से जुड़े मामलों की जांच और रिपोर्टिंग करते समय कानूनी कार्रवाई या आर्थिक दंड के जोखिम से बचने के लिए जरूरी खबरें प्रकाशित करने से पीछे हटें। बहरहाल, अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, जहां से भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता के बने और बचे रहने का रास्ता तय हो सकता है।

त्यौहार के समय जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतें परिवारों के बजट पर भारी

कल्याणी शंकर

त्यौहारी मौसम के दौरान आने वाली ये आर्थिक चुनौतियां उन छोटे व्यवसायों को प्रभावित कर सकती हैं, जो पूरी तरह से अपनी बिक्री पर निर्भर हैं। बढ़ती कीमतें मुनाफे के मार्जिन को कम कर सकती हैं, लेकिन ये हाथ से बनी वस्तुओं के महत्व को भी उजागर करती हैं। अनोखे और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद पेश करके, स्थानीय विक्रेता उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं जो असली और पारंपरिक चीजों की तलाश में हैं। भारत में त्यौहार एक महत्वपूर्ण परम्परा है, सिर्फ जश्न मनाने का मौका नहीं। इसलिए इस दौरान परिवार नए कपड़े, मिठाइयां, सजावट के सामान और उपहार खरीदने पर काफी पैसा खर्च करते हैं। हालांकि, बढ़ती कीमतें और महंगाई उपभोक्ताओं को अपना बजट और खरीदारी के तरीके बदलने पर मजबूर कर रही हैं। कई परिवार अब त्यौहारों को छोटे स्तर पर मना रहे हैं और सस्ती चीजें तलाश रहे हैं। मौसम के अनिश्चित मिजाज के कारण प्याज, लहसुन और अदरक जैसी जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल आया है। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है। इससे परिवहन और खनिज तेल की लागत बढ़ गई है। थोक बाजार में खनिज तेल की कीमतें पिछले साल के मुकाबले करीब 40 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। कोर महंगाई दर बढ़कर 4. 6 प्रतिशत हो गई है, जिसका असर खाने–पीने की चीजों, ईंधन, सेवाओं और अन्य सामानों की कीमतों पर पड़ रहा है। महंगाई को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए सिर्फ मौद्रिक नीति काफी नहीं है। इसके लिए समन्वित राजकोषीय उपायों की भी जरूरत है। इसमें नकदी प्रवाह का प्रबंधन, करों में बदलाव, और कृषि तथा आपूर्ति श्रृंखला में सुधार जैसे कदम शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति ने रेपोरेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी करके इसे 5.50 प्रतिशत कर दिया है। लगभग चार वर्षों में यह पहली बार है जब दरों में बढ़ोतरी की गई है। नीतिगत रुख को कड़ा से बदल कर नरपेक्ष करने का मतलब है कि निकट भविष्य में दरों में कटौती की संभावना कम है। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष और कमजोर मानसून के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे महंगाई को लेकर चिंताएं और गहरी हो गई हैं। नतीजतन, अगले एक साल में दरों में 100 बेसिस पॉइंट्स से ज्यादा की और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सितंबर में थोक महंगाई दर अगस्त के 9.92 प्रतिशत से बढ़कर 11.39प्रतिशत हो गई, जिसका मुख्य कारण तेल की कीमतों में 57.32 प्रतिशत की भारी वृद्धि थी। आरबीआई प्रमुख संजय मल्होत्रा ने कहा कि भविष्य में दरों में बढ़ोतरी आर्थिक विकास और महंगाई के रुझानों पर निर्भर करेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि सितंबर में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वीकार की गई कीमतों में बढ़ोतरी का, उपभोक्ताओं के लिए कीमतों और बिजली के बिलों पर कितना असर पड़ेगा? त्यौहारी मौसम के दौरान आने वाली ये आर्थिक चुनौतियां उन छोटे व्यवसायों को प्रभावित कर सकती हैं, जो पूरी तरह से अपनी बिक्री पर निर्भर हैं। बढ़ती कीमतें मुनाफे के मार्जिन को कम कर सकती हैं, लेकिन ये हाथ से बनी वस्तुओं के महत्व को भी उजागर करती हैं। अनोखे और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद पेश करके, स्थानीय विक्रेता उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं जो असली और पारंपरिक चीजों की तलाश में हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं और घरेलू नीतियों ने भारत में महंगाई पर काफी असर डाला है। सितंबर 2023 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 6.2 प्रतिशत बताई, जो इसके 2–6प्रतिशत के लक्ष्य दायरे से अधिक है। यह वृद्धि मुख्य रूप से भोजन, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की ऊंची कीमतों के कारण हुई है, जिसमें खाद्य महंगाई दर लगभग 7.8 प्रतिशत रही है। हाल ही में उठाए गए कदमों में खाना पकाने की गैस और अनाज जैसी आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स में कटौती और सब्सिडी देना शामिल है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने त्यौहारी मौसम से पहले आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने और महंगाई को कम करने के लिए खरीद के प्रयासों को तेज कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2026–27 के लिए 7.1 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर का



अनुमान लगाया है, जिसमें खुदरा महंगाई दर 5.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। हालांकि, साल की आखिरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर) में महंगाई बढ़कर 6 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। आरबीआई प्रमुख ने जोर देकर कहा कि भले ही अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन बढ़ती महंगाई अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। खुदरा विक्रेता इन आर्थिक रुझानों के अनुसार खुद को ढाल रहे हैं। वे आवश्यक वस्तुओं पर बंडल डील और छूट देकर ग्राहकों को पैसे की सही कीमत देने पर जोर दे रहे हैं। इस रणनीति से मध्यम श्रेणी के उत्पादों की बिक्री में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग में कमी आई है। स्थानीय बाजार और कारीगर इन आर्थिक चुनौतियों के बीच खुद को ढाल रहे हैं। उनके लिए त्यौहार का समय उनकी सालाना कमाई का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा होता है। इंस्टाग्राम और पिनटेरेस्ट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे सुझावों से भरे पड़े हैं, जो इस दौरान लोगों को रचनात्मकता और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सरकार ने खाना पकाने की गैस और अनाज जैसी जरूरी चीजों पर टैक्स में कटौती और सब्सिडी लागू की है। भारतीय खाद्य निगम ने भी आपूर्ति को लगातार बनाए रखने के लिए खरीद के प्रयासों को बढ़ाया है। इन उपायों का उद्देश्य त्यौहारी मौसम के करीब आते ही महंगाई को नियंत्रित करना है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ग्राहकों को कीमतों के रुझानों के बारे में जागरूक करने और खरीदारी के लिए दिशा–निर्देश देने के लिए अभियान शुरू किए हैं, ताकि आर्थिक चुनौतियां त्यौहारों की खुशियों पर भारी न पड़ें। शिपिंग में रुकावटों, उर्वरकों की ऊंची लागत और श्अलनीनोश के प्रभावों के कारण 2027 तक वैश्विक खाद्य महंगाई बढ़ने की आशंका है। इंडोनेशियाई चावल और भारतीय चीनी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, और मिस्र में ब्रेड की कीमतों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। स्टॉक में कमी और आयात बढ़ने के कारण कीमतों में और उछाल आने का अनुमान है। अपनी ताजा रिपोर्ट में, आरबीआई ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच महंगाई दर में अंतर को रेखांकित किया है, जिसमें ग्रामीण इलाकों में महंगाई अधिक देखी गई है। इन समस्याओं से निपटने के लिए, सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के भंडारण, प्रसंस्करण और वितरण के बुनियादी ढांचे में सुधार करना जरूरी है। इसके अलावा, घरेलू स्तर पर तिलहन का उत्पादन बढ़ाकर खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता कम करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि, लॉजिस्टिक्स और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में मौजूद बाधाओं को दूर करना आवश्यक है। औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने से अनौपचारिक क्षेत्र में कीमतों के उतार–चढ़ाव को कम करने में भी मदद मिल सकती है। इन चुनौतियों के बावजूद, त्यौहारों के मौसम में उपभोक्ता और व्यवसाय लगातार लचीलापन और रचनात्मकता दिखा रहे हैं।

महंगाई पर नियंत्रण और आर्थिक विकास की चुनौती

अरुण कुमार डनायक

अर्थव्यवस्था की चर्चा होते ही महंगाई, ब्याज दर, जीडीपी, राजकोषीय घाटा और आर्थिक विकास जैसे शब्द सामने आने लगते हैं। सरकार और रिजर्व बैंक अपनी राजकोषीय व मौद्रिक नीतियों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों और महंगाई को प्रभावित करते हैं। इन निर्णयों का आम नागरिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? महंगाई बढ़ने पर ब्याज दरें क्यों बढ़ाई जाती हैं और क्या केवल मौद्रिक उपायों से महंगाई नियंत्रित हो सकती है? ये प्रश्न आर्थिक नीतियों के आकलन में सहायक हैं। अर्थव्यवस्था किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों, व्यापारियों और निवेशकों के निर्णयों से संचालित होती है। लोग कितना खर्च, बचत और निवेश करेंगे तथा सरकार किन क्षेत्रों पर व्यय करेगी, इन सबका प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है। सरकार और केंद्रीय बैंक की नीतियों का उद्देश्य महंगाई पर नियंत्रण, निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन तथा टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना है। महंगाई का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होना है। जब खाद्य सामग्री और रोजमर्रा की वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें आमदनी की तुलना में तेजी से बढ़ती हैं, तो लोगों की वास्तविक क्रयशक्ति घट जाती है। महंगाई की दर में गिरावट का अर्थ कीमतों का कम होना नहीं, बल्कि उनके बढ़ने की गति धीमी पड़ना हैय इसलिए इससे आम लोगों को वास्तविक राहत मिलना जरूरी नहीं है। महंगाई कई कारणों से बढ़ सकती है। कभी बढ़ती मांग कीमतों पर दबाव डालती है, तो कभी पेट्रोलियम, ऊर्जा, परिवहन, मजदूरी और कच्चे माल की बढ़ती लागत उत्पादन को महंगा बना देती है। सूखा, बाढ़, युद्ध और वैश्विक आपूर्ति व्यवधान भी कीमतें बढ़ा सकते हैं। इसलिए महंगाई को किसी एक कारण या केवल सरकारी नीतियों का परिणाम मानना उचित नहीं है। महंगाई का प्रसार तब चिंता का विषय बनता है, जब मूल्य–वृद्धि कुछ वस्तुओं तक सीमित न रहकर अर्थव्यवस्था के व्यापक हिस्से में फैलने लगती है। महंगाई के प्रभाव को समझने के लिए अर्थशास्त्री उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलाव का आकलन करते हैं। महंगाई को नियंत्रित करने में भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय भूमिका होती है। उसका प्रमुख साधन रेपो दर है, जिसके माध्यम से वह बैंकों के लिए धन की लागत को प्रभावित करता है। रेपो दर बढ़ने पर व्यक्तिगत ऋणों की ईएमआई बढ़ सकती है और कारोबार के लिए ऋण महंगा हो सकता है। इससे परिवारों और कंपनियों के खर्च तथा निवेश में कमी आ सकती है, जिससे महंगाई नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ब्याज दरों का प्रभाव सभी पर एक समान और तत्काल नहीं पड़ता। ऋण महंगा होने से मांग घट सकती है, जबकि बचत और सावधि जमा पर मिलने वाला प्रतिफल बढ़ सकता है। फिर भी यदि महंगाई का प्रमुख कारण तेल, खाद्यान्न या अन्य वस्तुओं की आपूर्ति में कमी हो, तो केवल ब्याज दरें बढ़ाना पर्याप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में अत्यधिक सख्ती निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास को भी प्रभावित कर सकती है। रेपो दर के अलावा आरबीआई नकद आरक्षित अनुपात के माध्यम से बैंकों की जमा का वह हिस्सा निर्धारित करता है, जिसे नकदी के रूप में रखना अनिवार्य है। वैधानिक तरलता अनुपात के तहत बैंकों को जमा का एक निर्धारित हिस्सा नकदी, सोने और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद–बिक्री से भी आरबीआई बैंकिंग प्रणाली में धन और ऋण प्रवाह को प्रभावित करता है। वह विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर रुपये की अस्थिरता कम करने का प्रयास भी करता है, हालांकि इससे वैश्विक तेल कीमतों या बाहरी आपूर्ति संकटों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। मौद्रिक नीति की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि लोग और व्यवसाय भविष्य को कैसे देखते हैं। यदि उन्हें लगातार महंगाई बढ़ने की आशंका हो, तो वे अपने खर्च, वेतन और मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय उसी अनुसार लेने लगते हैं, जिससे महंगाई और बढ़ सकती है। इसके विपरीत, स्थिर कीमतों का विश्वास आर्थिक व्यवहार को संतुलित बनाता है। इसलिए रिजर्व बैंक के लिए स्पष्ट संवाद और नीतिगत विश्वसनीयता भी ब्याज दरों जितनी ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक सुस्ती के दौर में सरकार सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर रोजगार, आय और मांग को प्रोत्साहन दे सकती है। इसके विपरीत, व्यापक महंगाई की स्थिति में वह करों, सरकारी व्यय और सब्सिडी में बदलाव करके मांग तथा कीमतों के दबाव को संतुलित करने का प्रयास करती है। आयकर में राहत से लोगों की उपलब्ध आय बढ़ सकती है, जबकि जीएसटी में कटौती से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी आ सकती है। हालांकि, इन उपायों का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि राहत किस सीमा तक उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। साथ ही, करों में कटौती से सरकारी राजस्व घट सकता है, इसलिए सरकार को आम लोगों को राहत देने और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ता है। सरकारी खर्च विकास और जनकल्याण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण साधन है। बुनियादी ढांचे, कृषि, कौशल विकास और स्वास्थ्य पर निवेश से उत्पादकता, रोजगार और दीर्घकालीन विकास को बढ़ावा मिल सकता है। वहीं, कमजोर तबकों तक सामाजिक सहायता समय पर और पारदर्शी ढंग से पहुंचने से उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होती है। महंगाई से निपटने के लिए सरकार अल्पकाल में आपूर्ति सुधारने हेतु सार्वजनिक भंडार से अनाज जारी करने, आयात सुगम बनाने, जमाखोरी पर रोक लगाने और राज्यों के साथ समन्वय जैसे कदम उठा सकती है। वहीं, दीर्घकाल में सिंचाई, भंडारण, शीतगृह, खाद्य प्रसंस्करण और आपूर्ति श्रृंखला में निवेश से उत्पादन और उपलब्धता बढ़ाकर मूल्य दबाव को स्थायी रूप से कम किया जा सकता है। भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देश में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों और रुपये के मूल्य में उतार–चढ़ाव से आयात लागत तथा महंगाई प्रभावित होती है। इस निर्भरता को कम करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देना और निर्यात क्षमता को मजबूत करना आवश्यक है। आर्थिक नीतियों की प्रभावशीलता के लिए सरकार, रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के बीच समन्वय तथा कारोबारियों का विश्वास महत्वपूर्ण है। वाणिज्यिक बैंक जमा और ऋण नीतियों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। श्जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने, दंडात्मक प्रावधानों में उचित नरमी बरतने और कर अनुपालन को अधिक पारदर्शी बनाने जैसे कदम कारोबारी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के बीच केवल ब्याज दरों में बदलाव या कर राहत पर्याप्त नहीं है। महंगाई पर नियंत्रण, उत्पादक निवेश, रोजगार सृजन और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने वाली समन्वित नीति ही व्यापक आर्थिक हितों की पूर्ति कर सकती है। अंततरू आर्थिक नीतियों की सफलता का आकलन आम नागरिक की क्रयशक्ति, रोजगार के अवसरों और जीवन–स्तर में सुधार से किया जाना चाहिए।



कृति खरबंदा

के जन्मदिन पर याद करें उनकी ये 6 ऑन-स्क्रीन जोड़ियां

रोमांस से कॉमेडी तक दिखा अलग अंदाज

अभिनेत्री कृति खरबंदा ने अपनी फिल्मों के जरिए रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा जैसे अलग-अलग जॉनर में काम किया है। उनके जन्मदिन के मौके पर नजर डालते हैं उन छह फिल्मों पर, जिनमें उनकी जोड़ी अलग-अलग अभिनेताओं के साथ बनी। इन फिल्मों में कहीं रिश्तों की उलझनें देखने को मिलीं, तो कहीं प्यार, हंसी और भावनाओं से जुड़ी कहानियों ने दर्शकों का ध्यान खींचा। फिल्म 'राज रीबूट' में कृति खरबंदा इमरान हाशमी के साथ नजर आई थीं। हॉरर और सस्पेंस से भरपूर इस फिल्म में एक शादीशुदा रिश्ते के बीच रहस्यमयी घटनाएं सामने आती हैं। फिल्म की कहानी ने कृति को रोमांटिक भूमिकाओं से अलग एक ऐसे माहौल में काम करने का मौका दिया, जहां डर, रहस्य और रिश्तों की परेशानियां साथ-साथ चलती हैं।'गेस्ट इन लंदन' में कृति और कार्तिक आर्यन की जोड़ी ने रोमांटिक कॉमेडी का रंग दिखाया। फिल्म में रहने की एक अनपेक्षित व्यवस्था से ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, जो किरदारों की जिंदगी में हास्य और उलझनें लेकर आती हैं। दोनों कलाकारों ने कहानी में रोमांस और हल्के-फुल्के मनोरंजन का मेल पेश किया। कॉमेडी फिल्म 'पागलपंती' में कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट की जोड़ी नजर आई थी। फिल्म में दोनों के बीच की केमिस्ट्री के साथ उनकी असल जिंदगी की प्रेम कहानी भी इस जोड़ी को खास बनाती है। साथ काम करने के दौरान दोनों करीब आए और उनका रिश्ता आगे बढ़कर शादी तक पहुंचा। यही वजह है कि पर्दे पर उनकी जोड़ी को उनके प्रशंसक निजी जिंदगी के सफर से जोड़कर भी देखते हैं। 'शादी में जरूर आना' में कृति खरबंदा ने आरती शुक्ला का किरदार निभाया था, जबकि राजकुमार राव उनके साथ मुख्य भूमिका में थे। फिल्म प्यार, करियर की महत्वाकांक्षाओं, रिश्तों में आई दरार और कठिन फैसलों के इर्द-गिर्द घूमती है। कहानी में दोनों किरदारों के बीच बदलते रिश्ते कई भावनात्मक मोड़ लाते हैं। कृति के किरदार की जिंदगी में आने वाले उतार-चढ़ाव फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। फिल्म '14 फेरे' में कृति खरबंदा ने अदिति करवसरा की भूमिका निभाई थी और विक्रांत मैसी उनके साथ नजर आए। कहानी प्यार के साथ परिवार की उम्मीदों और सांस्कृतिक मतभेदों से पैदा होने वाली चुनौतियों को सामने लाती है। फिल्म में रोमांस और कॉमेडी के जरिए दिखाया गया है कि जब दो लोग साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो उन्हें पारिवारिक परिस्थितियों के बीच किस तरह रास्ता निकालना पड़ता है। फिल्म 'कारवां' में कृति खरबंदा रुमाना के किरदार में दिखाई दी थीं, जो अविनाश की पूर्व प्रेमिका होती है। फिल्म में उनकी भूमिका सीमित थी, लेकिन दुलकर सलमान के साथ उनकी मौजूदगी कहानी में एक अलग पहलू जोड़ती है। यह जोड़ी भले ही पर्दे पर ज्यादा समय तक नजर नहीं आई, लेकिन फिल्म में उनकी मुलाकात ने दर्शकों के सामने किरदारों के पुराने रिश्ते की झलक पेश की।

3 शेरों के बीच जंगल में रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट को किया प्रपोज, बताया- चूहे जैसा महसूस हो रहा था, सुनकर हस पड़े अमिताभ बच्चन

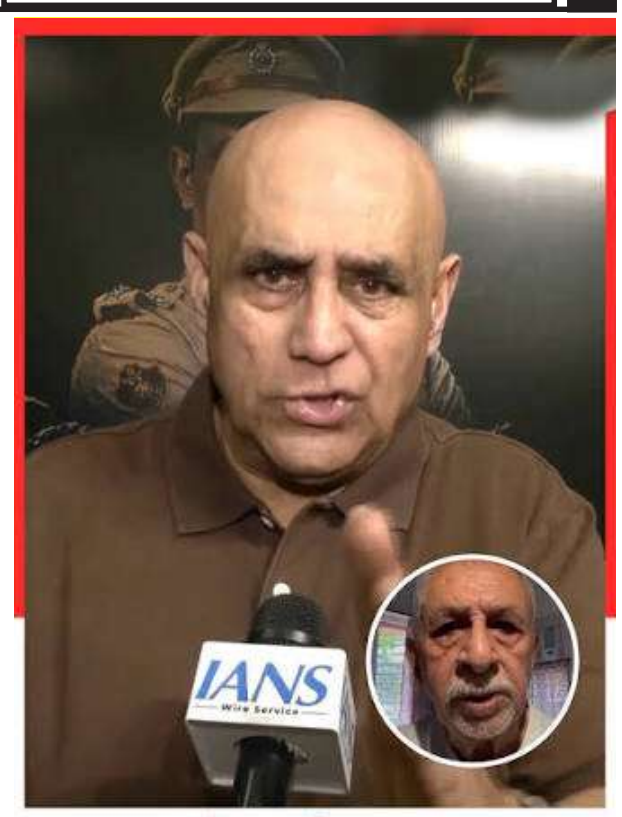


रणबीर कपूर का आलिया भट्ट को प्रपोज करना एक रोमांटिक पल होना था लेकिन कुछ ही दूरी पर तीन शेरों के खड़े होने की वजह से, अभिनेता के लिए स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो गई थी। उस खास पल को याद करते हुए, रणबीर ने बताया कि जब वह अपनी शेरनी (आलिया) को शादी के लिए प्रपोज कर रहे थे, तो उन्हें खुद एक चूहे जैसा महसूस हो रहा था। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति' में शामिल होने के दौरान, रणबीर ने बताया कि कैसे उन्होंने 2022 में केन्या के मसाई मारा की यात्रा के दौरान आलिया को प्रपोज करने की योजना बनाई थी। अमिताभ बच्चन से बात करते हुए, अभिनेता ने बताया कि उन्होंने पहले ही अपने गाइड और ड्राइवर से बात कर ली थी और उनसे जंगल के बीच कहीं गाड़ी रोकने के लिए कहा था। वह अपने साथ एक अंगूठी भी ले गए थे और चाहते थे कि वे दूर से ही इस प्रपोजल की तस्वीरें खींच लें। अपनी योजना के बारे में बताते हुए रणबीर ने कहा, "मैंने पहले ही अपने गाइड, जो ड्राइवर भी थे, उन्हें बता दिया था कि जंगल के बीच कहीं गाड़ी रोक देना। मैं एक अंगूठी साथ लाया था और मेरा इरादा घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करने का था। मैंने उनसे दूर से तस्वीरें खींचने के लिए कहा क्योंकि लड़कियों को तस्वीरें खिंचवाने का बहुत शौक होता है। इंस्टाग्राम पर डालने के लिए इसलिए मुझे लगा कि आलिया के लिए यह बहुत जरूरी था। उनकी यह बात सुनकर, शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने मजाक में कहा कि ऐसे खास पल का कोई सबूत तो होना ही चाहिए। उन्होंने कहा, पर सर, एक... सबूत तो होना चाहिए। इसके बाद रणबीर ने बताया कि असल में जो हुआ, वह उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। उनके पास अंगूठी तो थी, लेकिन लगभग 100 फीट की दूरी पर तीन शेर खड़े थे, जिससे यह रोमांटिक पल थोड़ा और डरावना हो गया। इस नजारे के बारे में बताते हुए एक्टर ने कहा, सबूत तो होना ही चाहिए. .. खैर, अंगूठी तो मेरे पास थी हीय मैं उसे घर से लेकर गया था। लेकिन सर, हालात कुछ ऐसे थे कि... लगभग 100 फीट दूर तीन नर शेर खड़े थे, मेरी शेरनी (आलिया) मेरे सामने खड़ी थी, और मैं एक चूहे की तरह घुटनों के बल बैठकर पूछ रहा था, बेबी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी ? तो, मुझे लगता है कि यह मेरी जिंदगी का एक बहुत ही अनोखा अनुभव था, जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। आलिया और रणबीर को अपनी हिट फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के दौरान एक-दूसरे से प्यार हो गया था। कुछ सालों तक डेट करने के बाद, दोनों ने अप्रैल 2022 में शादी कर ली। इसके बाद, नवंबर 2022 में उनके घर बेटी राहा का जन्म हुआ। कौन बनेगा करोड़पति का खास एपिसोड, जिसका नाम कौन बनेगा करोड़पति दिवाली स्पेशल है। 29 और 30 अक्टूबर को रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होगा।



पिया के नाम की ...निक जोनास के नाम की मेहंदी रचाकर प्रियंका चोपड़ा ने मनाया करवा चौथ, दिखाया खूबसूरत अंदाज

ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा जोनास हर साल की तरह इस बार भी करवा चौथ का त्योहार मनाती नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर अपनी हथेली पर लगी करवा चौथ स्पेशल मेहंदी की एक झलक साझा की। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, प्रियंका ने अपनी हथेली की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें लगी मेहंदी के डिजाइन में उनके पति निक जोनास का नाम शामिल था। उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, पिया के नाम की. .. करवा चौथ मनाने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं। अपनी एक और सोशल मीडिया स्टोरी में, अभिनेत्री ने मेहंदी को करीब से दिखाया और एक ऐसी पारंपरिक विधि के बारे में पूछा, जिससे मेहंदी का रंग गहरा हो जाता है। उन्होंने लिखा, सवाल यह है कि क्या चाशनी काम करेगी ? जो जानते हैं, वे समझ गए होंगे। जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि श्चाशनीश का मतलब चीनी के घोल से है। पारंपरिक रूप से, सूखी मेहंदी पर इसे लगाया जाता है ताकि मेहंदी का पेस्ट नम रहे और उसका रंग गहरा हो सके। मेहंदी का रंग गहरा करने के लिए अक्सर ऐसा किया जाता है। अमेरिकी गायक निक जोनास से शादी करने वालीं प्रियंका अक्सर विदेशों में भी अपनी परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश करती हैं। वह यह भी सुनिश्चित करती हैं कि उनकी बेटी मालती मैरी भारतीय परंपराओं और त्योहारों से जुड़ी रहे। इससे पहले, अभिनेत्री ने लॉस एंजिल्स स्थित अपने घर पर परिवार द्वारा मनाए गए दशहरा उत्सव की झलक भी साझा की थी। इस उत्सव में पूजा, शिवलिंग अभिषेक और हवन के साथ-साथ कन्या पूजन भी शामिल था। इस दौरान निक को अपनी बेटी मालती के पैर धोते हुए देखा गया।



सरकार पसंद नहीं तो चुनाव लड़े और जीत कर दिखाएं...नसीरुद्दीन शाह पर भड़के महाभारत के दुर्योधन पुनीत इस्सर

अभिनेता पुनीत इस्सर ने सरकार के खिलाफ टिप्पणी करने पर दिग्गज कलाकार नसीरुद्दीन शाह की आलोचना की है। उन्होंने नसीरुद्दीन पर चुनिंदा आलोचना करने का आरोप लगाया और राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए। नसीरुद्दीन को अपना सीनियर, शिक्षक और एक सम्मानित कलाकार बताते हुए, इस्सर ने आईएनएस से घ्कहा कि हालांकि हर किसी को अपनी राय रखने और सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें उन लोगों के खिलाफ भी बोलना चाहिए जो कथित तौर पर देश को बांटना चाहते हैं।

पुनीत ने आईएनएस से घ्कहा सबसे पहले तो, नसीरुद्दीन शाह हमारे सीनियर हैं, वे हमारे शिक्षक रहे हैं, उनका सम्मान है, वे एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जब आप अपनी बात रखते हैं, तो आपको चुनिंदा तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। आप दुनिया के कई मुद्दों पर बोलने वाले बन गए हैं, लेकिन कभी-कभी आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं, तब आप कुछ नहीं बोलते। एक तरफ, आप हर बात पर वामपंथी या नक्सलवादी विचारधारा के हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं। दूसरी तरफ, आप हर बात पर वामपंथी या नक्सलवादी विचारधारा के हिसाब से ही प्रतिक्रिया देते हैं। टुकड़े-टुकड़े गैंग, जेएनयू गैंग, जेल में बंद अपराधी, आतंकवादी... अगर आप ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, तो फिर आपका भारतीय होना कहां गया ? मेरा मतलब यह है कि आपको अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है, आपको सरकार के खिलाफ बोलने का भी अधिकार है। लेकिन अगर आपको मौजूदा सरकार पसंद नहीं है, तो आप मैदान में उतरें, चुनाव लड़ें, जीतें और सरकार को हरा दें। यह सरकार कोई मनमानी से नहीं बनी है, लोगों ने इसे चुना है। जनता ने चुनकर ही इन्हें सत्ता में भेजा है।

पुनीत ने नसीरुद्दीन शाह से चुनाव लड़ने के लिए कहा। तो आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, जो भी विचारध ारा हो, आप आइए और चुनाव लड़िए। चुनाव लड़ें, अपनी विचारधारा को सामने लाएं। चुनाव जीतकर सरकार बदल दें। आपको किसने रोका है ? जब हमारे देश में कोई समस्या आती है, तो आप चुप रहते हैं। आप उस पर कुछ नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि यह दिग्गज कलाकार तब चुप ही रहता है।"आप उस समय चुप रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि चुनिंदा मुद्दों पर आलोचना करना बहुत गलत बात है। मेरा मानना घ्है कि चुनिंदा आलोचना करना बहुत गलत है। जब राष्ट्रीय हित की बात आती है, तो जो लोग हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, जो देश के टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं, जो भारत-विरोधी बातें करते हैं, आप उनके खिलाफ अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते ? पुनीत ने अपनी बात खत्म करते हुए कहारू "तब आप गूंगे बन जाते हैं, और लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। आप ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहते हैं जो हमारे देश को बांटना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं। तो यह पूरी तरह से गलत है। आप हमारे सम्मानित नेता हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप मेरे प्रमुख रहे हैं, मेरे शिक्षक रहे हैं। लेकिन आपको केवल एक ही पक्ष की तरफ से बोलने का अधिकार नहीं है। बुधवार को नसीरुद्दीन ने सरकार के खिलाफ एक और तीखी टिप्पणी की। अभिनेता ने अपने फेसबुक पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वे कैमरे के सामने बात करते हुए नजर आ रहे हैं।

वीडियो में, उन्होंने खुद को दिमागी नक्सल के रूप में पेश किया। यह शब्द प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान इस्तेमाल किया था, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जनता के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा था। उन्होंने चल रहे विरोध ा प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए, जेएनयू के पुराने विरोध ा प्रदर्शनों से तुलना की और राष्ट्र-विरोधी और टुकड़े-टुकड़े गैंग जैसे शब्दों का उल्लेख किया।



बदलते मौसम में बीमारियों से बचाएगा आंवले का अचार, इम्यूनिटी को देगा सुपर बूस्ट! जानिए कैसे बनाएं आंवले का अचार

आंवला खाने से सेहत मस्त–मस्त रहती है। आंवले में विटामिन ए, बी और सी होते हैं और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके सेवन से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। बदलते मौसम में आंवले का सेवन करने से हेल्थ भी मस्त रहती हैं और बीमारियां भी दूर रहती है। खासकर बच्चे आंवले के सेवन करने से मना करते हैं, तो आप इस मजेदार तरीके से आंवला अचार बना सकते हैं, इसे सब पसंद करेंगे। अचार खाना पंसद हैं, तो इंस्टेंट आंवले का अचार बनाएं। आइए आपको आंवले का इंस्टेंट अचार बना सकते हैं।

आंवले का इंस्टेंट अचार बनाने की सामग्री

– आधा से एक किलो आंवला
– एक चम्मच राई
– एक चम्मच जीरा
– दो चम्मच धनिया
– आधा चम्मच मेथी
– काली मिर्च
– सौंफ एक चम्मच
– लाल मिर्च पाउडर
– सरसों का तेल
– हल्दी
– लाल मिर्च पाउडर
– नमक स्वादानुसार
– आठ से दस हरी मिर्च

इंस्टेंट आंवला अचार बनाने की रेसिपी

– इसके लिए आंवले को अच्छे से धोकर सुखा लें।

– अब आप इन आंवलों को प्रेशर कुकर में उबाल लें फिर उबलते पानी में डालकर हल्का नर्म पड़ने तक पकाएं। फिर गैस से उतारकर सारे आंवलों को छान लें।

– फिर बीजों को हटाकर आंवले के चार भाग करें और इसके बाद करीब दो घंटे तक धूप लग जाने दीजिए। ताकि इसका पानी खत्म हो जाए।

– एक पैन में सारे मसाले ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इसमें राई, जीरा, धनिया, मेथी, काली मिर्च, लाल मिर्च डालकर भून लें।

– अब इसको ग्राइंडर में पीस कर पाउडर बना लें।

– सरसों तेल को लें और इसे गैस पर पका लें। ताकि तेल का कच्चापन चला जाए।

– तेल गर्म होने के बाद इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और तैयार मसाले डालें और साथ ही आंवले को डालकर ऊपर से नमक डालकर मिक्स करें। बस तैयार है इंस्टेंट आंवले का अचार।

– इसके बाद आप कटी हुई ताजी हारी मिर्च को भी डाल दें। इससे आपके अचार का टेस्ट बढ़ जाएगा।



शॉर्ट नहीं अब शर्ट ड्रेस का है फैशन, जरूर करें अपने वॉर्डरोब में शामिल

कुछ समय पहले जहां क्रॉप टॉप के क्रेज सिर चढ़ कर बोल रहा था, वहीं इस सीजन फैशन मार्केट में शर्ट ड्रेसेज छाई हुई हैं। वैसे तो आमतौर पर शर्ट को ट्राउजर, पैंट्स, जीन्स, लेगिंग्स आदि के साथ पेयर किया जाता है लेकिन शर्ट की लेंथ अगर लंबी है तो उसे ड्रेस का नाम दे दिया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप कई तरह से स्टाइल कर सकते हैं और इस मौसम में तो यह कूल और सेफ ऑप्शन है। तो चलिए आज जानते हैं शर्ट ड्रेस को स्टाइल करने के तरीके।

कॉटन और सिल्क शर्ट ड्रेस है ज्यादा डिमांड में

शर्ट ड्रेसेज में आपको कई तरह के फैब्रिक मिल जाएंगे, जैसे कॉटन, सिल्क और डेनिम। कॉटन शर्ट ड्रेस को हर ऑकेजन में पहनी जा सकती है, वहीं सिल्क शर्ट ड्रेस को डेट नाइट जैसे खास मौकों पर कैरी कर सकते हैं। वहीं लाइट डेनिम वाली शर्ट ड्रेस भी दोस्तों के साथ आउटिंग जैसे मौकों पर अट्रैक्टिव लुक देती है। वैसे कुछ मौकों पर लिनेन फैब्रिक की शर्ट भी ग्लैमरस लगती है। दरअसल, ये फैब्रिक बॉडी को कूल बनाए रखते हैं, इसलिए ये समर में बेहतरीन ऑप्शन है।

इस तरह करें स्टाइल

हॉट और एलिगेंट लुक पाने के लिए शर्ट ड्रेस आपकी काफी मदद कर सकते हैं, बस जरूरत है इसके साथ सही अक्सेसरीज का चयन करने की। इस ड्रेस के साथ गोल्डन इयररिंग्स और ब्रेसलेट अच्छी लगती हैं। वहीं आप शर्ट ड्रेस के साथ स्नीकर्स शूज पेयर करके अपना लुक कम्पलीट कर सकती हैं।

लेयर करके भी पहन सकते हैं शर्ट ड्रेस

जरूरी नहीं है कि शर्ट ड्रेस को हमेशा सिंगल ही पहनें। आप इसे श्रग भी बना सकती हैं और एक ओवरसाइज शर्ट की तरह से इसे अपने बाकी आउटफिट्स के साथ भी पेयर कर सकती हैं। अगर आपने फ्लोई ड्रेस पहनी है, तो लेंथ को ध्यान में रखते हुए शर्ट ड्रेस चूज करें। इसे को–ऑर्ड सेट्स, जंपसूट्स, जीन्स–टी के साथ भी लेयर करके पहना जा सकता है।

ये कलर हैं ट्रेंड में

शर्ट ड्रेस में आजकल लाइम येलो, पीकॉक ब्लू जैसे कलर्स खूब डिमांड में हैं। वहीं पिंक जैसे ब्राइट कलर्स को नाइट टाइम में आप ट्राई कर सकते हैं।

बेल्ट के साथ शर्ट

वैसे तो आपको मार्कीट में कई तरह के डिजाइंस मिल जाएंगे, अगर आप कुछ अलग करने की सोच रही हैं तो बेल्ट लगी शर्ट ड्रेस आपकी मदद कर सकती है।

इसके कॉलर और स्लीव में बटन होते हैं। ड्रेस के कलर से डार्क या कंट्रास्ट करती बेल्ट आपके लुक को अट्रैक्टिव बनाने का काम कर सकती है। ये डिजाइन ग्रे और ब्राउन जैसे कलर में लोगों को ज्यादा लुभा रहा है।



शर्ट ड्रेस को कैरी करने का सही तरीका

–शर्ट ड्रेस को अपनी पसंद के मुताबिक मैक्सी, मिनी और मिडी हेमलाइन में ले सकते हैं।

– अगर शर्ट ड्रेस लंबी है तो स्किनी जींस और शूज पहनें।

– बोल्ड लुक के लिए ब्राइट ग्रीन, पिंक और ऑरेंज कलर को चूज करें।

– इंटरव्यू के लिए पहन रही हैं, तो लाइट ब्लू, वाइट व ग्रे कलर की शर्ट ही कैरी करें।



केले के छिलके का चमत्कार, रातभर इस तरीके से इस्तेमाल करने से मिलते हैं फायदे

हम जानते हैं कि केला खाने के लिए ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद लाभकारी है। यह शरीर को तुरंत एनर्जी, विटामिन्स और मिनरल्स प्रदान करता है। वर्कआउट करने वाले लोग भी इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केले का छिलका भी आपके लिए चमत्कारी फायदे ला सकता है?

दांतों को बनाएं सफेद और चमकदार

अगर आपके दांत पीले पड़ गए हैं या उनमें चमक नहीं है, तो केले का छिलका आपके लिए एक आसान घरेलू उपाय साबित हो सकता है। रोजाना केले के छिलके के अंदर के सफेद हिस्से को हल्के हाथों से अपने दांतों पर रगड़ें। इसमें मौजूद पोटैशियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज जैसे मिनरल्स दांतों की सतह पर जमी परत को साफ करते हैं और दांतों की नैचुरल व्हाइटनेस वापस लाते हैं। नियमित रूप से कुछ दिनों तक ऐसा करने से दांत साफ, चमकदार और मजबूत नजर आने लगते हैं।

स्किन कॉर्न्स (त्वचा के दाने) दूर करें

अगर आपकी त्वचा पर कॉर्न्स या हार्ड स्किन की समस्या है, तो केले का छिलका इसमें काफी मददगार साबित हो सकता है। इसके अंदर मौजूद एंजाइम्स और नैचुरल ऑयल्स त्वचा की कठोर परत को मुलायम बनाते हैं और धीरे–धीरे उसे हटाने में मदद करते हैं। इसके लिए केले के छिलके को प्रभावित जगह पर रखें, फिर उसे टेप से चिपकाकर ऊपर से मोजे पहन लें और रातभर ऐसे ही छोड़ दें। नियमित रूप से ऐसा करने से कॉर्न्स नरम होकर धीरे–धीरे खत्म हो जाते हैं और त्वचा फिर से मुलायम और स्वस्थ दिखने लगती है।

मुंहासों और दाग–धब्बों का इलाज

अगर आप मुंहासों, पिंपल्स या दाग–धब्बों से परेशान हैं, तो केले का छिलका एक प्राकृतिक उपाय है जो आपकी त्वचा को राहत दे सकता है। इसमें मौजूद ऐंटिऑक्सिडेंट्स, विटामिन सी और पोटैशियम त्वचा की गहराई से सफाई करते हैं और बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं। इसके लिए केले के छिलके के अंदरूनी सफेद हिस्से को हल्के हाथों से मुंहासों पर रगड़ें और 10–15 मिनट के लिए छोड़ दें। नियमित रूप से ऐसा करने से मुंहासे सूखने लगते हैं, दाग–धब्बे धीरे–धीरे हल्के होते हैं और चेहरा साफ, मुलायम और चमकदार दिखने लगता है।

काले घेरे कम करें

अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं और चेहरा थका हुआ दिखता है, तो केले का छिलका इस समस्या को कम करने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद विटामिन सी, विटामिन ई और ऐंटिऑक्सिडेंट्स त्वचा को पोषण देते हैं और डार्क सर्कल्स को हल्का करने में सहायक होते हैं। इसके लिए केले के छिलके के अंदरूनी हिस्से को आंखों के नीचे हल्के हाथों से लगाएँ और 20 मिनट तक रहने दें। इसके बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें। हफ्ते में 2–3 बार ऐसा करने से काले घेरे धीरे–धीरे कम होते हैं और आंखों के नीचे की त्वचा ताजगी और नमी से भर जाती है।

किन लोगों को नहीं करना चाहिए इस्तेमाल?

संवेदनशील त्वचा वाले लोग यदि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या किसी चीज से जल्दी जलन होती है, तो केले के छिलके का इस्तेमाल न करें। पहले हाथ पर थोड़ा लगाकर पैच टेस्ट कर लें।

एलर्जी वाले लोगः अगर आपको केले या लेटेक्स से एलर्जी है, तो छिलका लगाने से खुजली, लालपन या जलन हो सकती है। ऐसे लोग इसका उपयोग न करें।

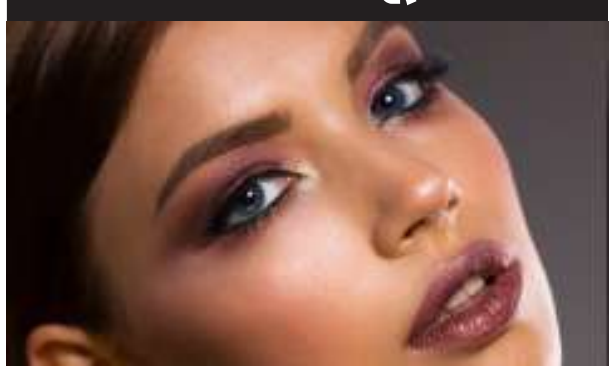
खुले जख्म या कट वाली जगह परः जहां स्किन फटी या कट लगी हो, वहां केले का छिलका न लगाएं, वरना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

तेलिया और एक्ने–प्रोन स्किन वालेः बहुत ऑयली स्किन पर छिलका लगाने से रोमछिद्र बंद हो सकते हैं, जिससे पिंपल्स बढ़ सकते हैं।

केले के छिलके को फेंकने की बजाय आप इसे सौंदर्य और सेहत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपकी त्वचा और दांतों के लिए सौंदर्य और स्वास्थ्य दोनों का खजाना साबित हो सकता है।

मेकअप से चुटकियों में छुपाएं ओपन पोर्स, पाएं फ्लॉलेस और स्मूथ चेहरा!

ओपन पोर्स के कारण मेकअप फ्लॉलेस नहीं दिखता। इस समस्या को दूर करने और स्मूथ चेहरा पाने के लिए, पहले त्वचा को अच्छे से साफ कर हाइड्रेट करें। फिर, सिलिकॉन-बेस्ड पोर-फिलिंग प्राइमर, कंसीलर और अंत में ट्रांसलूसेंट पाउडर का सही इस्तेमाल करें, जिससे मेकअप बेदाग और पोर्स छुपे हुए दिखेंगे।



कई बार जब मेकअप करते हैं, तो स्किन स्मूद बिल्कुल नहीं होती है। ओपन पोर्स की वजह मेकअप फ्लॉलेस नहीं दिखता है। स्किन पर ओपन पोर्स होने के कारण मेकअप का लुक एकदम बेकार हो जाता है। वैसे तो इन पोर्स से बचने के लिए स्किन केयर किया जाता है लेकिन फिर भी यह चेहरे से पूरी तरह गायब नहीं होते हैं। अब आपने मेकअप को स्मूद और फ्लॉलेस बनाने के लिए इन मेकअप टिप्स को जरुर फॉलो करें।

फेस को अच्छे से क्लीन करें

मेकअप करने से पहले यह जरुरी होता है कि स्किन को अच्छे से साफ कर लिया जाए। इसके लिए माइल्ड क्लींजर की मदद लें और इसे हाइड्रेट करने के लिए आप ऑयल–फ्री और नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइश्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी स्किन ऑयली है तो जेल बेस्ड मॉइश्चराइजर लगाएं। क्योंकि गंदगी, ऑयल और ड्राई स्किन के कारण ओपन पोर्स ज्यादा दिखते हैं। स्किन हाइड्रेट रहे और फुल टाइट दिखती है, जिससे पोर्स छोटे लगते हैं।

सिलिकॉन बेस्ड पोर–फिलिंग प्राइमर का यूज करें

जब आप मेकअप करें तो प्राइमर का यूज करें। यह लाइट और सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होना चाहिए। आप प्राइमर को पोर्स वाली जगहों जैसे कि नाक, गाल व माथे पर लगाएं। यह आपकी स्किन को स्मूद बनाएगा। इसके साथ ही यह आपके ओपन पोर्स को छिपाने मदद करेगा।

कंसीलर को स्मार्टली अप्लाई करें

यह प्रकार का स्मार्ट हैक है। कंसीलर की मदद से पोर्स को छिपाया जा सकता है। ऐसे में जहां पोर्स नजर आ रहे हैं वहां पर कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कंसीलर नहीं है, तो आप फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। यह आपकी स्किन को नेचुरल और स्मूद लुक देगा। इसे आप स्पॉन्ज या उंगली से हल्के हाथों से अप्लाई करें। इसके बाद आप ट्रांसलूसेंट पाउडर को सेट कर सकते हैं। यह पाउडर एक्स्ट्रा ऑयल सोखता है और इससे आपके ओपन पोर्स कम नजर आएंगे। इसका यूज करते समय ध्यान रखें कि इसका ज्यादा यूज न करें, वरना आपकी स्किन केकी लगेगी और ऊपर से पोर्स दिखने लगेंगे।

संक्षिप्त

लागत बढ़ने और कमजोर मांग से अंबुजा सीमेंट्स का शुद्ध लाभ दूसरी तिमाही में 90 प्रतिशत गिरा

अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जुलाई–सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 90 प्रतिशत घटकर 236 करोड़ रुपये रह गया। ईंधन और लॉजिस्टिक लागत बढ़ने तथा मानसून के कारण मांग प्रभावित होने की वजह से अदाणी समूह की इस कंपनी के परिचालन मार्जिन पर दबाव पड़ा। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष 2025–26 की समान तिमाही में 2,336 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया था। इसमें 1,697 करोड़ रुपये की आयकर प्रावधान को हटाने की राशि भी शामिल थी। अंबुजा सीमेंट्स ने जारी नतीजों में बताया कि सितंबर तिमाही में कंपनी की परिचालन आय 0.2 प्रतिशत बढ़कर 9,197 करोड़ रुपये रही। वहीं कर पूर्व आर्य (ईबीआईटीडीए) 27.9 प्रतिशत घटकर 1,271 करोड़ रुपये रह गई। इस दौरान सीमेंट बिक्री मात्रा 0.6 प्रतिशत घटकर सालाना आधार पर 1.65 करोड़ टन रही। कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) विनोद बहेती ने कहा, ''मौसम से जुड़ी और बाहरी चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2026–27 की दूसरी तिमाही तथा पहली छमाही में हमारा प्रदर्शन गुणवत्ता आधारित वृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।।'' इस बीच, शेयरधारकों ने एसीसी लिमिटेड और ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड के अंबुजा सीमेंट्स में विलय की प्रस्तावित योजना को मंजूरी दे दी है। हालांकि, इस प्रक्रिया को नियामकीय, वैधानिक और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मंजूरी मिलना बाकी है। कंपनी को वित्त वर्ष 2026–27 में इसके पूरा होने की उम्मीद है।

Google की मूल कंपनी Alphabet का शुद्ध लाभ घटा, तीसरी तिमाही में 26.17 अरब डश्वलर रहा

गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक. ने तीसरी तिमाही में राजस्व में मजबूत वृद्धि दर्ज की, लेकिन कंपनी की कमाई वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रही है। इसके बाद बुधवार को कंपनी का शेयर करीब नौ प्रतिशत टूट गया। कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू स्थित कंपनी ने बताया कि जुलाई–सितंबर तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 26.17 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 34.98 अरब डॉलर से कम है। हालांकि, इस दौरान कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 25 प्रतिशत बढ़कर 127.58 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इसके बावजूद यह विश्लेषकों के 127.97 अरब डॉलर के औसत अनुमान से कम रहा। कंपनी ने प्रति शेयर 2.12 डॉलर की कमाई दर्ज की। तिमाही के नतीजों पर इक्विटी निवेश में 8. 7 अरब डॉलर के नुकसान का भी असर पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार, यह स्पष्ट नहीं था कि कंपनी की प्रति शेयर कमाई के आंकड़े की विश्लेषकों के करीब 3.01 डॉलर के अनुमान से सीधे तुलना की जा सकती है या नहीं। गूगल और अल्फाबेट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुंदर पिचाई ने एक बयान में तिमाही को मजबूत बताया। पिचाई के मुताबिक, कंपनी का व्यापक तकनीकी ढांचा उसके विभिन्न कारोबारों में वृद्धि को गति दे रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी के कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित सहायक ऐप जेमिनी के उपयोगकर्ताओं की संख्या एक अरब तक पहुंच गई है। उन्होंने इसे गूगल के इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ने वाला उत्पाद बताया।

Jio Platforms का शेयर 5% से ज्यादा उछला, मार्केट कैप 13.72 लाख करोड़ पार

जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के शेयर में बृहस्पतिवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में तेजी जारी रही। कंपनी का शेयर बीएसई और एनएसई पर पांच प्रतिशत से अधिक चढ़ गया। इस बढ़त के साथ कंपनी का बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) बढ़कर 13.72 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। बीएसई पर कंपनी का शेयर 5.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,490 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर शेयर 5.09 प्रतिशत चढ़कर 1,489.70 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इससे बीएसई पर कंपनी का बाजार पूंजीकरण 66,903.61 करोड़ रुपये बढ़कर 13,72,145.59 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का शेयर अपने 1,119 रुपये के निर्गम मूल्य से दोनों प्रमुख शेयर बाजार में 33 प्रतिशत से अधिक ऊपर कारोबार कर रहा है। जियो प्लेटफॉर्म्स ने बुधवार को शेयर बाजार में शानदार शुरुआत की थी। कंपनी का शेयर निर्गम मूल्य से करीब 27 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ था। इसके साथ ही कंपनी बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की दूसरी सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी बन गई थी। कंपनी का शेयर बीएसई और एनएसई पर 1,358 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ था, जो इसके निर्गम मूल्य से 21.36 प्रतिशत अधिक था। बीएसई पर शेयर 26.66 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,417.35 रुपये पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान इसने 1,423.80 रुपये का उच्चतम स्तर भी छुआ था। एनएसई पर शेयर 26. 67 प्रतिशत चढ़कर 1,417.50 रुपये पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान इसने 1,423.90 रुपये का उच्चतम स्तर हासिल किया था। बुधवार के कारोबारी सत्र के अंत में जियो प्लेटफॉर्म्स का बाजार पूंजीकरण 13 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया था। कंपनी बाजार मूल्यांकन के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद दूसरे स्थान पर रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 15.92 लाख करोड़ रुपये है। जियो प्लेटफॉर्म्स ने बाजार पूंजीकरण के लिहाज से भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को पीछे छोड़ दिया है। जियो प्लेटफॉर्म्स का 30,213 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) कुल 22.19 गुना अभिदान के साथ बंद हुआ था। सार्वजनिक निर्गम और एंकर निवेशकों के आवंटन को मिलाकर कुल मांग सात लाख करोड़ रुपये से अधिक रही थी। आईपीओ पूरी तरह से 27 करोड़ नए शेयरों का निर्गम था। इसके लिए मूल्य दायरा 1,065 रुपये से 1,119 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। आईपीओ से पहले कंपनी ने 19 अक्टूबर को 212 एंकर निवेशकों से करीब 8,110 करोड़ रुपये जुटाए थे।

टीम इंडिया के ओपनर अभिषेक शर्मा ऑकलैंड T20I में 49 रन बनाकर तोड़ेंगे बड़ा रिकॉर्ड

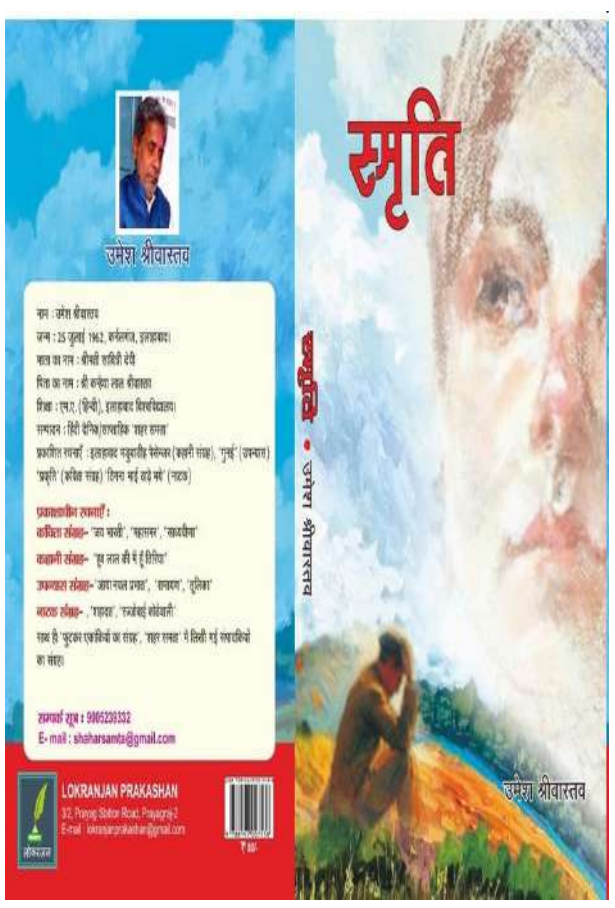


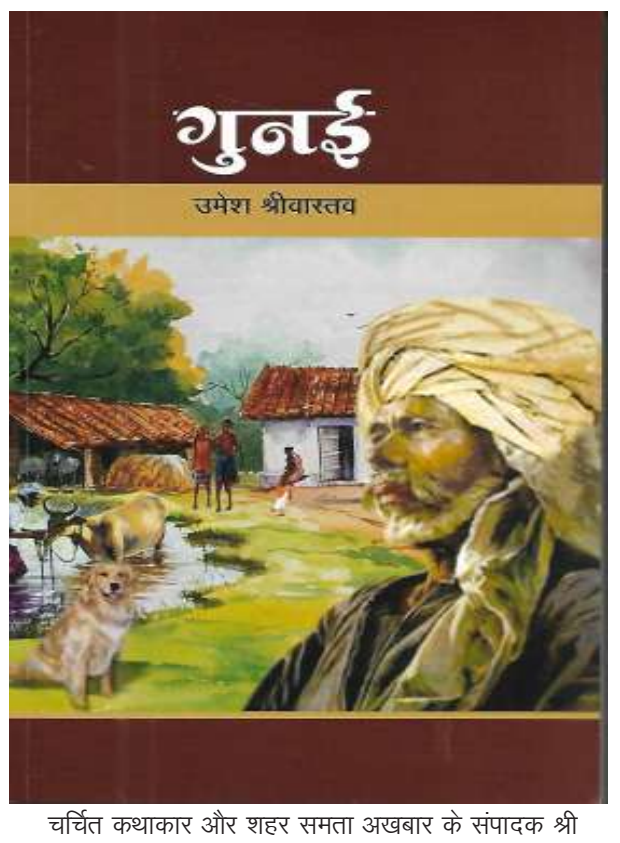
भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे T20I में बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हैं। वह केएल राहुल और हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़कर T20I में भारत के चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने से महज 49 रन दूर हैं। अभिषेक ने 70 मैचों में 2,240 रन बनाए हैं। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़कर ज20ि में भारत के लिए चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने से सिर्फ 49 रन दूर हैं। शुक्रवार को ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले चौथे T20I मैच में, अभिषेक के पास भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन T20I खिलाड़ियों में से एक के रूप में अपनी जगह पक्की करने का मौका है। तीसरे T20I में 199 रनों का पीछा करते हुए 38 गेंदों पर 113 रन बनाने वाले अभिषेक, पहले ही एक भारतीय के तौर पर सबसे ज्यादा टी20 शतक (11) लगाने का बड़ा रिकॉर्ड बना चुके हैं, जिसमें उन्होंने दिग्गज विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। अब, ऑकलैंड T20I में अभिषेक के पास रन बनाने के मामले में और आगे बढ़ने का मौका है। 70 T20I मैचों में, अभिषेक ने 69 पारियों में 33.43 की औसत और 196.83 के स्ट्राइक रेट से 2,240 रन बनाए हैं। इसमें चार शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं, और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन है। अपने ज20ि डेब्यू के दो साल से कुछ ही समय बाद, वह फिलहाल भारत के लिए ज20ि में छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अगर अभिषेक अपने खाते में 26 रन और जोड़ लेते हैं, तो वह केएल राहुल (72 मैचों में 2,265 रन, जिसमें दो शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं) को पीछे छोड़कर भारत के लिए पांचवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। वहीं, 49 और रन बनाने पर वह हार्दिक पांड्या (138 मैचों में 2,288 रन, जिसमें नौ अर्धशतक शामिल हैं) को पीछे छोड़कर भारत के लिए T20I में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। भारत के लिए T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष तीन खिलाड़ी हैं: रोहित शर्मा (159 मैचों में 4,231 रन, जिसमें पांच शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं), विराट कोहली (125 मैचों में 4,188 रन, जिसमें एक शतक और 38 अर्धशतक शामिल हैं) और सूर्यकुमार यादव (113 मैचों में 3,272 रन, जिसमें चार शतक और 25 अर्धशतक शामिल हैं)। रोहित और विराट जैसे सुपरस्टार्स, जो भारत के लिए शुरुआती रन–मशीन और मैच–विनर रहे, उनके बाद अभिषेक का इस सूची में चौथे स्थान पर आना, भारतीय T20I बल्लेबाजी की पीढ़ियों का एक बेहतरीन क्रम बनाता है। इसके बाद आते हैं 360–डिग्री हिटर सूर्यकुमार, जिन्होंने 2020 के दशक में अपने आक्रामक स्ट्राइक रेट, हर तरह के शॉट्स खेलने की क्षमता और निरंतरता के दम पर भारतीय T20I बल्लेबाजी को एक नए स्तर पर पहुँचाया। अभिषेक, सूर्यकुमार के दौर की ही देन हैं, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट में एक बेहद आक्रामक और बेखौफ सिक्स–हिटर के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने अपने T20I करियर में अब तक 158 छक्के लगाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट लगभग 200 के करीब रहा है।

न्यूजीलैंड को लगा झटका, फर्ग्यूसन और मैट हेनरी भारत के खिलाफ T20I सीरीज के बाकी मैचों से बाहर

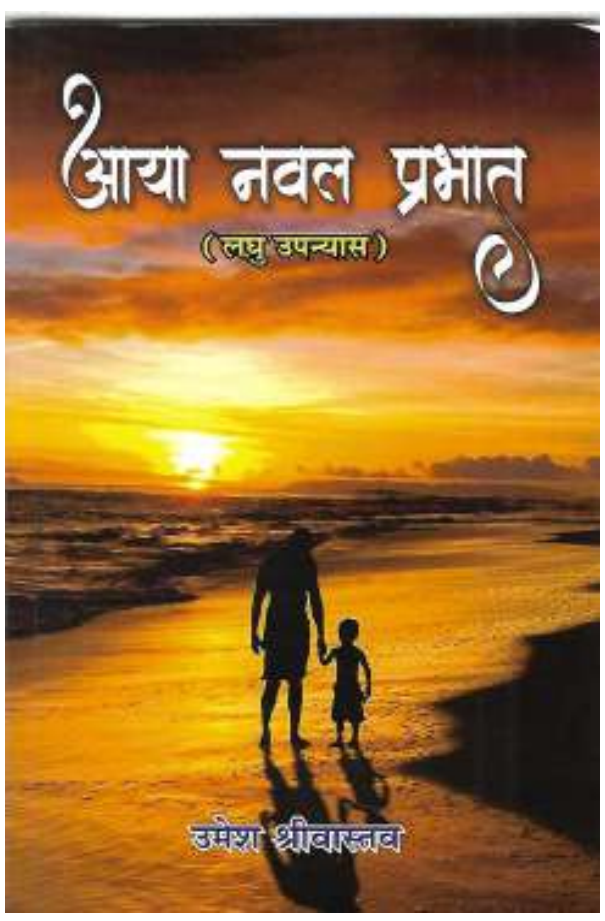
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी चोट के कारण भारत के खिलाफ पांच मैचों की ज20ि सीरीज के बाकी मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। फर्ग्यूसन की पिंडली और हेनरी की जांघ में चोट लगी है। कीवी टीम ने अंतिम दो टी20 मैचों के लिए मैट फिशर को टीम में शामिल किया है।

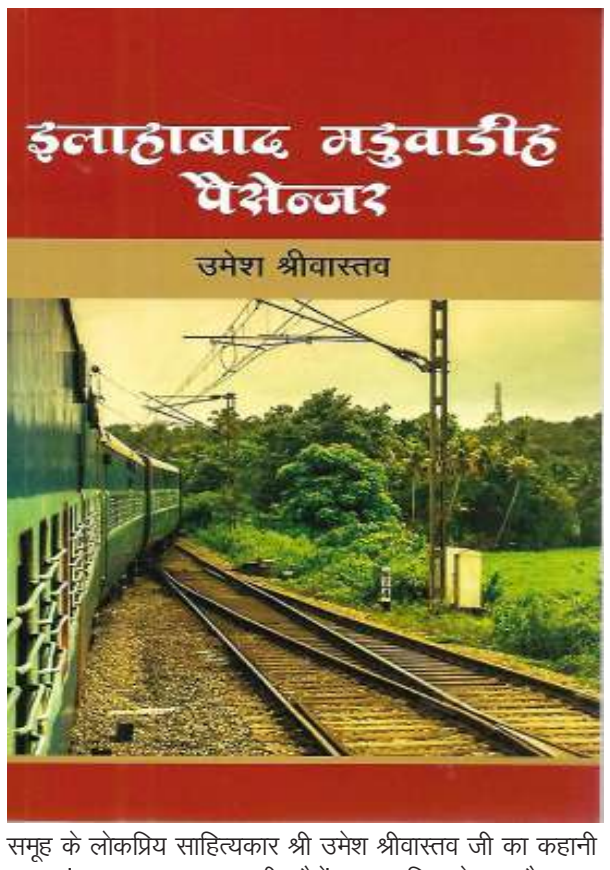
चोट के कारण न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी भारत के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे ज20ि मैच के दौरान फर्ग्यूसन की पिंडली (calf) में चोट लग गई, जिसके चलते वे कम से कम एक हफ्ते तक मैदान से बाहर रहेंगे। वहीं, उसी मैच में मैट हेनरी की जांघ (quad) में चोट लग गई, जिससे उन्हें ठीक होने में दो हफ्ते तक का समय लग सकता है। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ आखिरी दो T20I मैचों के लिए तेज गेंदबाज मैट फिशर को अपनी टीम में शामिल किया है। उन्हें उम्मीद है कि 4 नवंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज तक फर्ग्यूसन और हेनरी फिट हो जाएंगे। चौथा T20I शुक्रवार को और आखिरी T20I रविवार को खेला जाएगा। ICC के हवाले से न्यूजीलैंड के कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि हम लॉकी और मैट के लिए बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में चोटें तो लगती ही रहती हैं, लेकिन जब आपको कुछ मैच छोड़ने पड़ें, तो यह बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अच्छी बात यह है कि मैट पहले से ही बाकी ज20ि मैचों से बाहर रहने वाले थे, क्योंकि आगे गर्मियों में उनका काफी व्यस्त शेड्यूल है। हमें उम्मीद है कि वह व्क्ष मैचों में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मुझे पता है कि लॉकी कल ईडन पार्क में दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम के सामने खेलने के लिए बहुत उत्साहित थे, लेकिन वह व्क्ष मैचों में वापसी करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।



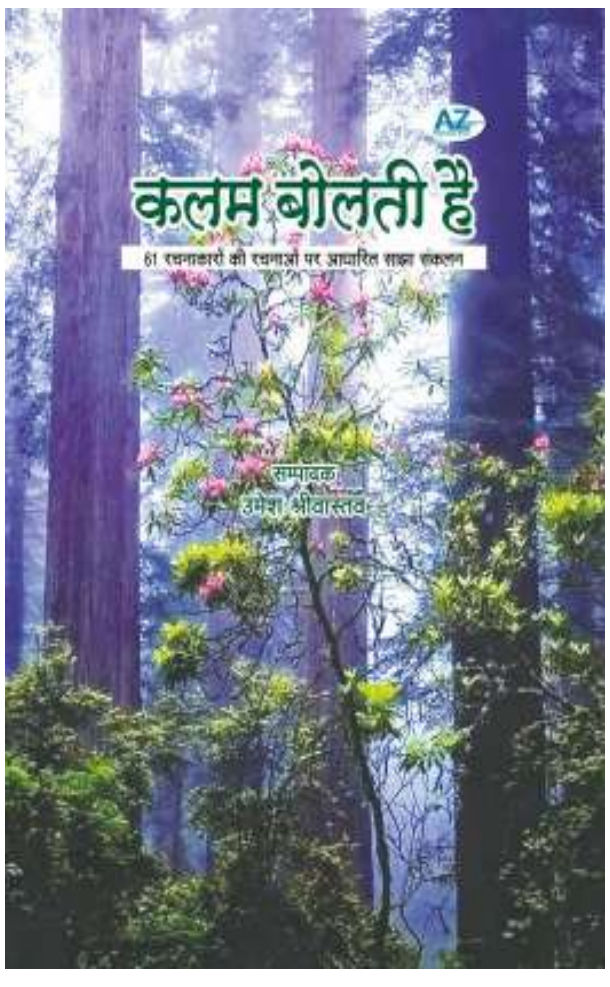


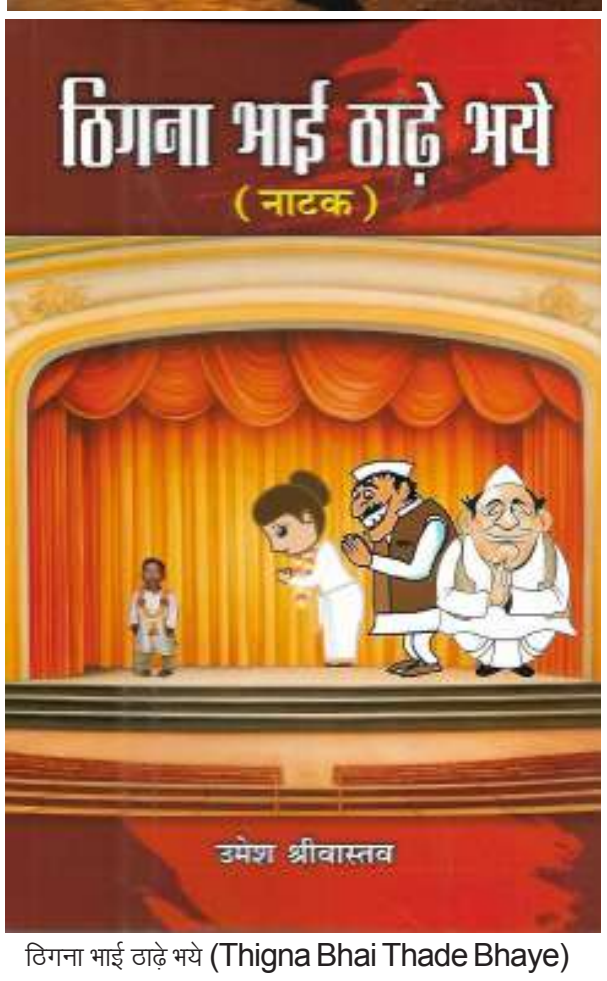
चर्चित कथाकार और शहर समता अखबार के संपादक श्री उमेश श्रीवास्तव जी का ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखा बहु प्रतीक्षित





समूह के लोकप्रिय साहित्यकार श्री उमेश श्रीवास्तव जी का कहानी संग्रह इलाहाबाद मडुवाडीह पैसेंजर प्रकाशित हो गया है। उमेश श्रीवास्तव जी को बहुत बधाई एवम शुभकामना।





ठिगना भाई ठाढ़े भये (Thigna Bhai Thade Bhaye)

बुरे फंसे नेतन्याहू! नहीं मिला बहुमत, अब अरब पार्टियां बनेंगी किंगमेकर



इजराइल के चुनाव नतीजों ने सियासत को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाना आसान नहीं है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लेकिन उनके पूरे गठबंधन को बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटें नहीं मिल पाई। दूसरी तरफ नैतन्याहू को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहा विपक्ष भी अपने दम पर बहुमत से कुछ कदम दूर है। अब तस्वीर में तीसरा अहम पक्ष और वो है अरब नेतृत्व वाली पार्टियां जिनके पास कुल 19 सीटें जाती दिख रही हैं। अब इनका समर्थन ही तय कर सकता है कि इजराइल में अगली सरकार किसकी बनेगी? यानी मुस्लिम पार्टियों के पास किंग मेकर बनने का मौका है। नेतन्याहू के पास सरकार बनाने के कौन–कौन से विकल्प हैं? क्या नेतन्याहू अपने विरोधी अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बना सकते हैं? अगर कोई भी बहुमत नहीं जुटा पाया तो क्या इजराइल को फिर से चुनाव में जाना पड़ेगा। आइजराइल में 27 अक्टूबर को संसदीय चुनाव हुए। देश की संसद को नेससेट कहा जाता है जिसमें कुल 120 सदस्य होते हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। 29 अक्टूबर की सुबह तक उपलब्ध मतगणना के आधार पर सीटों का जो अनुमान सामने आया वह कुछ इस प्रकार है। नेप्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को कुल 53 सीटें मिलती दिख रही हैं। जिनमें नेत्याहू की पार्टी लिक्विड को 26 सीटें, यूनाइटेड टोरा जुडि को सात सीटें, शास को सात सीटें, ओत्समा को सात सीटें मिल रही हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिल रही हैं। जिनमें नेत्याहू के खिलाफ खड़े पीएम उम्मीदवार गादी आइसन कोर्ट की याशर पार्टी को 21 सीटें नफ्ताली बेनेट की बीहत पार्टी को 12 सीटें द डेमोक्रेट्स को आठ सीटें एगडोर लिबरमैन की इजराइल बेतुन को सात सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं अब आते हैं तीसरे विकल्प पर जिसके भरोसे पक्ष या विपक्ष में से किसी की इजराइल की सत्ता में वापसी हो सकती है। यानी जो त्रिशंकु का किरदार अदा करेगा। दरअसल अरब नेतृत्व वाली पार्टी में जॉइंट लिस्ट को 12 सीटें और राम पार्टी को सात सीटें मिलती दिख रही हैं। ऐसे में अरब पार्टियों के पास 19 सीटें हैं। इजरायली अरब पार्टियों को मिली बढ़त बातचीत में काफी अहम साबित हो सकती है, हालांकि विपक्ष के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने की उनकी इच्छा अभी भी स्पष्ट नहीं है। वामपंथी और अरब–बहुसंख्यक जॉइंट लिस्ट के प्रमुख यूसुफ जबरीन ने कहा कि मतदाताओं ने नेतृत्व में बदलाव की इच्छा जताई है। उन्होंने नेतन्याहू के विरोधियों को चुनौती दी कि वे उनके गठबंधन के साथ बातचीत करें। उन्होंने आगे कहा जो कोई भी नेतन्याहू की खून–खराबे वाली सरकार का एक ठोस और सच्चा विकल्प देना चाहता है, उसे हमसे बात करनी होगी। बाद में जबरीन ने एएफपी (।थ्च) को बताया कि वह नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष के नेतृत्व वाले प्रशासन के साथ सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन मौजूदा हालात में किसी सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होने की संभावना को उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में, खासकर गाजा में चल रहे युद्ध, वेस्ट बैंक में बस्तियों और अन्य मुद्दों को देखते हुए, इजरायली सरकार के गठबंधन का हिस्सा बनने की कोई संभावना नहीं दिखती। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अरब सांसद गठबंधन के बाहर से समर्थन दें, उससे आइसेनकोट के खेमे को अल्पमत सरकार चलाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस बात पर संदेह बना हुआ है कि क्या ऐसी सरकार इतनी स्थिर होगी कि लंबे समय तक टिक सके। चुनाव प्रचार के दौरान नेतन्याहू ने बार–बार चेतावनी दी कि अरब पार्टियों का प्रभाव बढ़ सकता है। बाद में उनकी लिकुड पार्टी ने अरब सूचियों पर चुनाव ष्चुरानेष् का आरोप लगाया। पार्टी का दावा है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ष्भ्रष्टाचार, धमकियों, हिंसा, झूठ और प्रतिबंधित सॉफ़्टवेयरष् का इस्तेमाल किया गया। पार्टी ने सार्वजनिक रूप से कोई सबूत तो नहीं दिया, लेकिन कहा कि वे इसे अधिकारियों के सामने पेश करेंगे। हालाँकि सरकार बनाने में अरब पार्टियाँ निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं, लेकिन विपक्ष के कुछ धड़े उनके साथ काम करने से हिचकिचा रहे हैं। इज़राइल की मुख्य वामपंथी पार्टी के नेता और आइसेनकोट के सहयोगी, यायर गोलान ने इस रुख से अलग हटते हुए अरब सांसदों के साथ सहयोग करने की वकालत की है।

संक्षिप्त

ईरान के सुरक्षा प्रमुख को जे.डी. वेंस ने भेजा पत्र, डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं शांति वार्ता

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने ईरान के सुरक्षा प्रमुख को पत्र लिखा है। यह कदम शांति वार्ता को फिर से शुरू करने और नवंबर में होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद किसी नए अमेरिकी सैन्य हमले को टालने की एक कोशिश है। डोनाल्ड ट्रम्प ने संकेत दिया है कि संघर्ष फिर से शुरू करने के लिए यही समय–सीमा है। अखबार के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के निर्देश पर यह पत्र ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख मोहसेन रेज़ाई को भेजा गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस संदेश और उसके बाद अमेरिकी तथा ईरानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत का मुख्य उद्देश्य किसी संभावित शांति समझौते की शर्तों को तय करने के बजाय, बातचीत के लिए एक रूपरेखा तैयार करना था। यह राजनयिक पहल ऐसे समय में सामने आई है जब महीनों से रुकी हुई बातचीत के बाद फिर से तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। खबरों के अनुसार, वाशिंगटन ने खाड़ी के कई अरब देशों से कहा है कि वे 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद ईरान के खिलाफ एक संभावित ष्संक्षिप्त लेकिन तीव्र सैन्य अभियानष् के लिए तैयार रहें। हालांकि, अखबार ने इस चर्चा से जुड़े लोगों के हवाले से बताया है कि ट्रम्प ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है कि ईरान के खिलाफ कोई नया सैन्य अभियान शुरू किया जाए या नहीं। अमेरिका और इज़राइल ने फरवरी के अंत में ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया था, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में भारी अस्थिरता पैदा हो गई और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में भी बाधा आई। इसके जवाब में, ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) से जहाजों की आवाजाही बंद कर दी है। यह एक बेहद अहम समुद्री मार्ग है, जिससे दुनिया की लगभग एक–पांचवीं तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (स्छळ) की आपूर्ति होती है। इसके अलावा, अमेरिका ने भी ईरानी बंदरगाहों की अपनी नौसैनिक घेराबंदी जारी रखी है। ईरानी सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका की ओर से कोई नया हमला होता है, तो ईरान की तरफ से और भी बड़ा जवाबी कदम उठाया जा सकता है। इसमें अमेरिका से जुड़े बुनियादी ढांचे, जैसे कि डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (।ै) सुविधाओं को निशाना बनाया जा सकता है। तेहरान ने कूटनीति (डिप्लोमेसी) के रास्ते पर आगे बढ़ने की इच्छा जताई है।

पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते पर मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्रीमारिया दीदी ने उठाए सवाल

माले। पाकिस्तान के साथ रक्षा और साइबर सुरक्षा संबंधों को मजबूत करते हुए, मालदीव को सहयोग से मिलने वाले तात्कालिक लाभ से आगे बढ़कर, क्षेत्रीय स्थिरता, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि पर इसके व्यापक प्रभावों के संबंध में विचार करना चाहिए। मालदीव एक छोटा देश है, लेकिन रणनीतिक रूप से इसका महत्व अधिक है। हिंद महासागर के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर स्थित होने, एक विशाल समुद्री क्षेत्र होने और काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन पर निर्भर अर्थव्यवस्था होने के कारण हमारा देश प्रमुख भू–राजनीतिक हितों के केंद्र–बिंदु पर स्थित है। हमारे जैसे छोटे देश के लिए विदेश नीति का मतलब केवल दोस्ती बढ़ाना या समझौतों पर हस्ताक्षर करना नहीं है। इसका उद्देश्य अपनी संप्रभुता की रक्षा करना, अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित रखना और यह सुनिश्चित करना कि बड़ी ताकतों के बीच की प्रतिद्वंद्विता हमारे लिए बोझ न बन जाए। राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू की 20 से 22 अक्टूबर तक की पाकिस्तान की राजकीय यात्रा की गहन समीक्षा की जानी चाहिए। इस दौरान दोनों देशों के बीच 20 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान–प्रदान हुआ था। यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हुई। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, व्यापार, कृषि और पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग से वास्तविक अवसर मिलते हैं। हालांकि रक्षा, समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को लेकर हुए समझौते, भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार जारी तनाव के माहौल में मालदीव की रणनीतिक दिशा को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करते हैं। सवाल यह नहीं है कि मालदीव को पाकिस्तान के साथ संबंध बनाए रखने चाहिए या नहीं। पाकिस्तान के साथ संबंध रखना चाहिये।

क्यूबा पर अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ UNGA प्रस्ताव का भारत ने किया समर्थन

भारत ने क्यूबा के खिलाफ अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंधों को समाप्त करने की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। भारत ने यह दोहराया कि कैरेबियाई देश को अपनी विकास आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करने के लिए इन प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की 193 सदस्यीय महासभा ने बुधवार को इस प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें 130 देशों ने पक्ष में मतदान किया, 17 ने विरोध में मतदान किया और 25 देश अनुपस्थित रहे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर सौम्या नायर ने भारत का वक्तव्य देते हुए कहा कि महासभा ने बार–बार प्रतिबंधों को समाप्त करने का आह्वान किया है और उन कानूनों एवं विनियमों को खारिज किया है जिनके बाह्यक्षेत्रीय प्रभाव होते हैं, जो अन्य राष्ट्रों की संप्रभुता तथा उनके लोगों की प्रगति व समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना, मतदाताओं से बदलाव के लिए वोट करने की अपील की



वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 'उम्मीद और बदलाव' का अपना लगभग दो दशक पुराना संदेश दोहराते हुए मतदाताओं से आग्रह किया कि वे 'गैर–गंभीर' राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी पर लगाम लगाने के अपने आखिरी और सबसे बेहतरीन मौके का इस्तेमाल करें। पूर्व राष्ट्रपति ने बुधवार शाम अटलांटा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें पहले से ही महसूस हो रहा है कि ''बदलाव की हवा चल रही है'' और लोग ''कुछ नया पाने के लिए बेहद उत्सुक हैं।'' उन्होंने डिस्कवरी सेंटर में जमा हुए हजारों डेमोक्रेटिक समर्थकों से कहा, ''ये लोग गंभीर नहीं हैं। और इनकी इसी गैर–गंभीरता की कीमत हम सभी चुका रहे हैं।'' उनके 45 मिनट के भाषण के दौरान वहां मौजूद समर्थक लगातार उनका उत्साह बढ़ाते रहे। अमेरिकी सीनेटर के तौर पर ओबामा 2008 में देश के 44वें राष्ट्रपति चुने गए थे और यह उनका पहला कार्यकाल था। ओबामा की इस जीत में उनकी प्रभावशाली भाषण कला और उम्मीद के उस संदेश का योगदान था जो उनके चुनाव अभियान के नारे ''हां, हम कर सकते हैं'' और बदलाव के उनके आह्वान में झलकता था। ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय 'व्हाइट हाउस' की भव्य सजावट की तुलना सद्दाम हुसैन (इराक के पूर्व राष्ट्रपति) द्वारा लोकप्रिय अमेरिकी रेस्तरां श्रृंखला 'चीजकेक फैक्टरी' को सजाने से की थी। 'चीजकेक फैक्टरी' अपनी शानदार सजावट के लिए मशहूर है। इसके बाद ट्रंप प्रशासन द्वारा की गई आलोचनाओं का भी ओबामा ने करारा जवाब दिया। ओबामा ने कहा, ''सद्दाम हुसैन वाली बात से उन्हें परेशानी नहीं हुई। लेकिन चीजकेक फैक्टरी वाली बात से उन्हें बहुत निराशा हुई।'' उन्होंने याद करते हुए कहा कि 'व्हाइट हाउस' ने वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट तक से चीजकेक फैक्टरी के सामने संवाददाता सम्मेलन करने को कहा था। भीड़ ने जब उनके समर्थन में नारेबाजी शुरू की तो ओबामा ने समर्थकों से अपना गुस्सा वोट में बदलने और तीन नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव में बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, ''वे आपकी नारेबाजी को नहीं सुन सकते, लेकिन आपका वोट सुन सकते हैं।'' उन्होंने महंगाई से जुड़े मुद्दे उठाए और ट्रंप पर राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल करके मुनाफा कमाने का आरोप लगाया। ओबामा ने कहा, ''हमने कभी ऐसा राष्ट्रपति नहीं देखा जो अनुचित लाभ देने के लिए इतना उतावला हो।'' उन्होंने कहा, ''इस शख्स ने पद पर रहते हुए अरबों डॉलर कमाए हैं। समझिए कि आज के समय में ऐसा पहले नहीं हुआ है।'' उन्होंने ट्रंप पर आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर कभी ध्यान नहीं देने का आरोप भी लगाया। ओबामा अमेरिकी सीनेटर जॉन ओसॉफ, अटलांटा की पूर्व मेयर और गवर्नर पद की उम्मीदवार कीशा लांस बॉटम्स तथा चुनाव लड़ रहे अन्य डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे थे। ओबामा ने कहा, ''जब आपने मेरी तरह कई चुनावों में प्रचार किया हो, तो आप समझ सकते हैं कि कोई चुनाव थोड़ा अलग कब होता है। ऐसा चुनाव, जिसमें लोग कुछ नया पाने के लिए, कुछ बेहतर पाने के लिए इतने उत्सुक हों और लगातार परेशानियों से इतने तंग आ चुके हों कि आप जहां भी जाएं, वहां बदलाव की हवा चलती महसूस हो।'' उन्होंने कहा, ''जॉर्जिया, इस समय मुझे यही महसूस हो रहा है। छह दिन में आपके पास ऐसा करने का मौका है।''

'राम' तय करेंगे इजरायल में किसकी बनेगी सरकार? कौन हैं अरब पार्टियां, किनके हाथों में है कमान

इज़राइल के संसदीय चुनाव के जो शुरुआती नतीजे सामने आए हैं, उसने वहां के पूरे सियासी समीकरण को उलटकर रख दिया है। 120 सदस्यों वाली नेसेट में बहुमत के लिए 61 सीटें चाहिए, लेकिन न तो नेतान्याहू की सत्ताधारी लॉबी इसे छू पाई और न ही गादी आइजनकोट का विपक्षी गठबंधन। इस राजनीतिक गतिरोध के बीच सबसे चौंकाने वाला मोड़ यह है कि इज़राइल की अरब–बहुल पार्टियां कुल 19 सीटें जीतकर सत्ता के केंद्र में आ खड़ी हुई हैं। श्जॉइंट लिस्टश और श्राश्अमश्ये दो ऐसी ताकतें हैं जिनकी विचारधारा भले ही जुदा हो, लेकिन इज़राइल में अगली सरकार किसके सहारे टिकेगी, यह अब पूरी तरह इनके रुख पर निर्भर करता है।

इज़राइल की अरब पार्टियां कौन सी हैं?

इज़राइल की आबादी में अरब नागरिकों की हिस्सेदारी लगभग एक–पांचवां हिस्सा है। वे राष्ट्रीय चुनावों में वोट डाल सकते हैं और नेसेट (इज़राइली संसद) के लिए अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं। हालांकि, लंबे समय से उन्हें आवास, सार्वजनिक सेवाओं और नगरपालिका फंडिंग जैसे क्षेत्रों में असमानता का सामना करना पड़ा है। 2026 के चुनाव में हिस्सा लेने वाली मुख्य अरब



राजनीतिक ताकतों में मंसूर अब्बास की श्राअमश (ट्ंउ) और श्जॉइंट लिस्टश (श्रवपदज स्पेज) शामिल हैं। श्जॉइंट लिस्टश में हदाश (भ्ंकै), ताअल (ज्ंस) और बलाद (ठंसंक) जैसे दल शामिल हैं। राजनीतिक प्रभाव हासिल करने के लिए ये दोनों अलग–अलग तरीके अपना रहे हैं।

राअमरू मंसूर अब्बास का व्यावहारिक दृष्टिकोण

राअम, या यूनाइटेड अरब लिस्ट, मंसूर अब्बास के नेतृत्व वाली एक इस्लामी–रूढ़िवादी पार्टी है। यह अरब समुदायों के लिए बेहतर सार्वजनिक सेवाओं और आर्थिक अवसरों की वकालत करती है, साथ ही अरब नागरिकों के सामूहिक अधिकारों को मान्यता देने की भी मांग करती है। इसकी प्राथमिकताओं में संगठित अपराध से निपटना, आवास और बुनियादी ढांचे में सुधार करना, शैक्षिक असमानताओं को कम करना और अरब नगरपालिकाओं के लिए अधिक संसाधन जुटाना शामिल है। यह पार्टी फिलिस्तीनी राज्य के गठन, कब्जे की समाप्ति और इजरायली बस्तियों को हटाए जाने का भी समर्थन करती है।

अब्बास ने गठबंधन की राजनीति में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। उनका तर्क है कि अरब सांसद, इजरायली सरकारों से पूरी तरह दूर रहने के बजाय, उनके साथ बातचीत करके ठोस लाभ हासिल कर सकते हैं। 2021 में, श्राआमश (ट्ंउ) इजरायली सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होने वाली पहली स्वतंत्र अरब पार्टी बनी, जिसने नफ्ताली बेनेट और यायर लापिड के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन किया।

चीन की चापलूसी में पाक ने रोकी ताइवानी फ्लाइट, भारत ने बोला– हम उड़ाएंगे!

पाकिस्तान चीन का पिछलग्गू है, इस बात को तो पूरी दुनिया अच्छे से जानती है। लेकिन ताइवान के मामले पर भारत ने जो कहा है जो करने की बात कही है वो बताता है कि भारत एक जिगरा वाला देश है। चीन के वन चाइना पॉलिसी के समर्थन में पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण पूरी दुनिया में उसकी थूथू हो रही है। उसने एक घिनौना कदम उठाया। चीन का पिछलग्गू बनने के लिए पाकिस्तान ने ताइवान के ही एयरलाइंस के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया। इस कदम के बाद ताइवान की प्रमुख विमानन कंपनियों को यूरोप जाने वाली उड़ानों का रास्ता बदलना पड़ा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई है। पाकिस्तान ने उसके मुताबिक ब्लूमबर्ग के मुताबिक कि पाकिस्तान ने ताइवान की एयरलाइंस को अपने हवाई क्षेत्र से उड़ान भरने गुजरने की जो अनुमति है उसको देना बंद कर दिया है। हाथ जोड़ लिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लेकर जानकारी है कि उन्होंने इस खबर की पुष्टि कर दी है और कहा है कि देश का विमानन विभाग वन चाइना पॉलिसी का पालन करता है और केवल मुख्य चाइना मेनलैंड चाइना की एयरलाइंस को पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान भरने की अनुमति देता है। उनके मुताबिक जो बात कही जा रही है कि पाकिस्तान ने सिर्फ चीनी एयरलाइंस के लिए अपने हवाई मार्ग खोले रखे हैं। चाइना ने जैसे ही पेंचें कसी इनकी ये पीछे–पीछे हो लिए। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्रालय से यह सवाल पूछ लिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बताइए आपका क्या रुख है ताइवान को लेकर? ताइवान से अगर विमान भारत आएगा तो आप क्या करेंगे? भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से यह सवाल किया गया था। उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि भारत और ताइवान के बीच सीधी हवाई सेवा की संभावना पर जो है सवाल है उस पर आप क्या करेंगे?यह खबर भी ऐसे ही वक्त में आई है जब यह पूरा मामला चल रहा है। तो उसको लेकर जो अपनी नीति है और जो बातें कही गई तो उन्होंने इसका बहुत स्पष्ट जवाब दिया है । उन्होंने कहा है कि भारत और ताइवान के बीच सीधे उड़ान की योजना जो है उन्हें लगता है कि अगर उड़ाने सीधी होंगी तो वह चलेंगी। उसके पीछे जो है वह कोई कदम



नहीं लेने वाले हैं। भारत न् अपने तेवर साफ कर दिए हैं। इशारा चीन को भी है कि हम पाकिस्तान की तरह पिछल्लगू नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान की एयरलाइंस ने बीते वीकेंड से ही बताया जा रहा है कि अपने उड़ान मार्ग बदलने शुरू कर दिए थे। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट है फ्लाइट रडार। ताइवान की प्रमुख विमान कंपनियां ने तकरीबन 25 अक्टूबर से ही पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं किया है। यानी कि उस एरिया का इस्तेमाल करना उन्होंने बंद कर दिया है। एशिया और यूरोप के बीच संचालित उनकी कम से कम एक दर्जन जो उड़ाने हैं वो रूस के ऊपर से होकर गुजर रही हैं। पाकिस्तान लंबे समय से वन चाइना पॉलिसी का समर्थक रहा है और इसमें वन चाइना पॉलिसी का मामला है नहीं। पाकिस्तान को चाहिए पैसा, इनको चाहिए समर्थन, इनको चाहिए हथियार, इनको चाहिए प्रोपोगेंडा का समर्थन। पाकिस्तान के इस तमाशे का अगर कोई समर्थन करता है तो उस देश का नाम चीन है। इस बात में किसी को कोई दो राय नहीं है।



संस्थापक
स्व.कन्हैया लाल
स्व.श्रीमती साधना
सम्पादक
उमेश चंद्र श्रीवास्तव
प्रबन्ध सम्पादक
अरविन्द पाण्डेय
संयुक्त सम्पादक
अनंत श्रीवास्तव
संयुक्त सम्पादक (तकनीकी)
केशव श्रीवास्तव
विधि सलाहकार
कल्पना श्रीवास्तव

शहर समता
स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक उमेश चन्द्र श्रीवास्तव द्वारा कम्पीटेन्ट बिजनेस सर्विसेज, विष्णु पदम कुटीर 115डी/2ई लूकरगंज, इलाहाबाद से मुद्रित कराकर 289/238ए,कर्नलगंज इलाहाबाद से प्रकाशित
सम्पादक
उमेश चन्द्र श्रीवास्तव
मो.नं.9005239332
आर.एन.आई.नं.
यूपीएचआईएन/2004/22466
Email : shaharsamta@gmail.com
इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के अधीन ही होंगे।